सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 63, नई दिल्ली । बुधवार, 15 मई 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

आपको खेल के नियम सीखने होंगे और फिर आपको किसी और से बेहतर खेलना होगा ।

03 दिल्ली में 15 मई को ग्रेजुएशन के लिए होने वाली सीयूईटी परीक्षा स्थगित...
06 क्या कहते हैं जीएसटी के आंकड़े ?
08 सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी के चुनाव पर रोक लगाने की मांग पर विचार से किया इनकार,

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कनेक्टविटी की समस्या हुई दूर , दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से जून तक जुड़ेगा

नोएडा एयरपोर्ट कनेक्टिविटी यमुना प्राधिकरण (यमुना अथॉरिटी) ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सड़क कनेक्टिविटी में आ रही बाधाओं को मंगलवार को दूर कर दिया। तालाब के कारण दयानतपुर में सड़क को एलिवेटेड बनाने का फैसला किया गया है। इसके कारण बढ़ी लागत को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण वहन करेगा। जून तक यह सड़क बनकर तैयार हो जाएगी।

संजय बाटला

यमुना प्राधिकरण ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सड़क कनेक्टिविटी में आ रही बाधाओं को मंगलवार को दूर कर दिया। तालाब के कारण दयानतपुर में सड़क को एलिवेटेड बनाने का फैसला किया गया है। इसके कारण बढ़ी लागत को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण वहन करेगा। जून तक यह सड़क बनकर तैयार हो जाएगी।

ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Noida International Airport) की सड़क कनेक्टिविटी में आ रही बाधाओं को मंगलवार को दूर कर दिया। तालाब के कारण दयानतपुर में सड़क को एलिवेटेड बनाने का फैसला किया गया है।

इसके कारण बढ़ी लागत को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण वहन करेगा। जून तक यह सड़क बनकर तैयार हो जाएगी। इसके बनने से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस-वे (Delhi Mumbai Expressway) से सीधे कनेक्टिविटी हो जाएगी।

इसके साथ ही यमुना एक्सप्रेस-वे के कार्गो टर्मिनल को जोड़ने के लिए सड़क निर्माण का काम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंप दिया है। तीस मीटर चौड़ी यह सड़क आठ माह में बनकर तैयार होगी।

पहले चरण का निर्माण अंतिम दौर में

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का निर्माण अंतिम दौर में हैं। अक्टूबर से यात्री सेवाओं की शुरूआत हो जाएगी। एयरपोर्ट की सड़क कनेक्टिविटी की परियोजनाओं पर भी काम तेज हो गया है। एयरपोर्ट को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस-वे से कनेक्टिविटी के लिए 31 किमी लंबा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे बनाया जा रहा है। यह बल्लभगढ़ में एक्सप्रेस-वे को कनेक्ट करेगा।

जमीन पर कब्जा दिलाने की समस्या दूर हुई

इसके निर्माण में गौतमबुद्ध नगर में अमरपुर पलाका व फलैदा बांगर गांव में बाधा आ रही थी। एक्सप्रेस-वे वन विभाग की जमीन से होकर गुजर रहा है। इस जमीन के पट्टे होने के कारण कब्जा मिलने में अड़चन आ रही थी। यमुना प्राधिकरण, एनएचएआई, प्रशासन के अधिकारियों के मौजूदगी में 2.4 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा दिलाने की बाधा को दूर किया गया।

तालाब पर एलिवेटेड रोड बनेगा

इसके साथ ही यमुना एक्सप्रेस-वे से नोएडा एयरपोर्ट के प्रवेश द्वार तक बनने वाली 750 मीटर लंबी सड़क के एलाइन्मेंट में दयानतपुर गांव में तालाब आ रहा है। यहां एलिवेटेड रोड बनाने का फैसला किया गया है। इससे निर्माण लागत बीस करोड़ रुपये बढ़ जाएगी। एनएचएआई ने इसके लिए सहमति दे दी है। सड़क की चार लेन का निर्माण जून तक पूरा हो जाएगा। अगस्त तक आठ लेन शुरू हो जाएंगी।

यमुना प्राधिकरण सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि एयरपोर्ट के उत्तर व पूर्व में तीस मीटर चौड़ी सड़क निर्माण का काम एनएचएआई करेगा। 8.2 किमी लंबी सड़क के निर्माण में 63 करोड़ रुपये खर्च होंगे। आठ माह में सड़क का निर्माण पूरा हो जाएगा। इस सड़क के बनने से यमुना एक्सप्रेसवे से कार्गो टर्मिनल से जुड़ जाएगा। इसके लिए एनएचएआई के साथ जल्द अनुबंध हस्ताक्षर होगा।

ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे के इंटरचेंज निर्माण के लिए कंपनी को भेजा पत्र

ईस्टर्न परिफेरल एक्सप्रेस-वे व यमुना एक्सप्रेस-वे को जोड़ने के लिए जगनपुर अफजलपुर गांव में इंटरचेंज का निर्माण करने वाली देव एस कंपनी को पत्र भेजा गया है। इंटरचेंज निर्माण के लिए कंपनी का चयन 2019 में हुआ था, लेकिन जमीन न मिलने के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया।

इसके चलते व डिजायन में बदलाव के कारण परियोजना की लागत 75 करोड़ से बढ़कर 122 करोड़ रुपये हो गई। दिसंबर में मुख्य सचिव डीएस मिश्रा ने निर्माण कार्य का शुभारंभ किया था, लेकिन मिट्टी कार्य के लिए कंपनी ने अतिरिक्त रकम की मांग की थी। एनएचएआई ने यह रकम देने से इन्कार कर दिया। यमुना प्राधिकरण ने कंपनी को पत्र भेजकर बुधवार तक जवाब मांगा है कि वह कार्य को करने के लिए तैयार है या नहीं, अन्यथा अन्य विकल्प तलाशा जाएगा।

वीआईपी के लिए अलग बनेगी सड़क

यमुना एक्सप्रेस-वे से नोएडा एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए वीआईपी एक्सेस मार्ग बनेगा। इसका निर्माण भी एनएचएआई करेगा। इस मार्ग का उपयोग वीआईपी व आपातकालीन स्थिति में किया जाएगा। मार्ग के लिए जमीन जल्द एनएचएआई को उपलब्ध कराई जाएगी।

अब भरी सड़कों पर देना होगा ड्राइविंग स्किल टेस्ट ! इस राज्य में डीएल के लिए सख्त नियम लागू

परिवहन विशेष न्यूज

केरल। मोटर वाहन विभाग (एमवीडी) ने ड्राइविंग टेस्ट के नियमों में कई बड़े बदलाव किए हैं। इस नए नियम के मुताबिक अब ड्राइविंग लाइसेंस आवेदकों को रियल लाइफ ड्राइविंग टेस्ट देना होगा। केरल में अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि केरल मोटर वाहन विभाग (एमवीडी) ने ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के नियमों में कई बड़े बदलाव किए हैं। यहां तक कि आवेदकों को अब वास्तविक जीवन में ड्राइविंग टेस्ट देना होगा, यानी आपको व्यस्त ट्रैफिक के बीच गाड़ी चलाकर अपनी ड्राइविंग स्किल साबित करनी होगी। इसके अलावा टेस्ट नियमों में कुछ अन्य बदलाव भी किए गए हैं। हाल ही में केरल मोटर वाहन विभाग (एमवीडी) द्वारा आदेश जारी किया गया था। जिसके मुताबिक अब ड्राइविंग लाइसेंस आवेदकों को वास्तविक व्यस्त सड़क पर ड्राइविंग टेस्ट देना अनिवार्य होगा. इसके अलावा विभाग ने एंगुलर पार्किंग, पैरेलल पार्किंग, जिग-जैग ड्राइविंग जैसे कई टेस्ट अनिवार्य कर दिए हैं। इस सर्कुलर में आवेदकों को 'H' टेस्ट देने से पहले ग्रेडिएंट टेस्ट से गुजरना होगा। आपको बता दें कि यह नियम नए ड्राइविंग लाइसेंस आवेदकों या इसे रिन्यू कराने वालों दोनों पर लागू होगा। नए नियमों में यह प्रावधान जोड़ा गया है कि 15 साल से ज्यादा पुरानी किसी भी कार का इस्तेमाल ड्राइविंग टेस्ट के लिए नहीं किया जाएगा। **इस नियम के मुताबिक, टेस्ट के दौरान टू-व्हीलर सेगमेंट में उन्हीं गाड़ियों को शामिल किया जाएगा जिनकी इंजन क्षमता 95 सीसी या उससे ज्यादा होगी। इसके अलावा चार पहिया वाहन ड्राइविंग टेस्ट में इलेक्ट्रिक और ऑटोमैटिक कारों को शामिल नहीं किया जाएगा।** इस नए नियम के मुताबिक, टेस्टिंग करने वाले वाहनों में डैशबोर्ड

कैमरा और व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (जीपीएस) लगाना अनिवार्य होगा। मौके पर मौजूद ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर को ड्राइविंग टेस्ट की रिकॉर्डिंग करनी होगी, जिसके लिए उसे अपने साथ एक मेमोरी कॉर्ड भी रखना होगा. यह रिकॉर्डिंग एमवीडी सिस्टम में स्थानांतरित कर दी जाएगी। इतना ही नहीं, ड्राइविंग टेस्ट देने वाले आवेदक को अगले 3 महीने तक रिकॉर्डिंग की कॉपी के तौर पर मेमोरी कॉर्ड अपने पास रखना भी अनिवार्य होगा।

ड्राइविंग स्कूल एसोसिएशन ने किया विरोधः हाल ही में केरल मोटर ड्राइविंग स्कूल इंस्ट्रक्टर्स एंड वर्कर्स एसोसिएशन ने इस सर्कुलर को केरल हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी. दरअसल, एसोसिएशन इन नए बदलावों को चुनौतीपूर्ण मान रहा है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (आईएनटीयूसी), सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीआईटीयू) और ऑल केरल ड्राइविंग स्कूल ओनर्स एसोसिएशन से संबद्ध यूनियनों सहित कई ड्राइविंग स्कूल संघों ने राज्य भर में ड्राइविंग परीक्षणों का बहिष्कार किया है और हड़ताल पर चले गए हैं। **यह देखना दिलचस्प होगा कि केरल मोटर वाहन विभाग (एमवीडी) द्वारा जारी किया गया यह नया नियम पूरे देश में लागू होता है या नहीं।**

चुनाव ड्यूटी से लौटी बीएस 6 बसें, दिल्ली रूट के यात्रियों को मिलेगी राहत

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। औरैया रोडवेज डिपो में 70 बसें 18 रूटों पर संचालित हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बसों का चुनाव ड्यूटी में जाना लगातार बना हुआ है। दिल्ली रूट पर बीएस-6 बसों से ही परिवहन हो पाता है। दिल्ली में बीएस-4 बसों की आवाजाही पर रोक है। ऐसे में पिछले दिनों गईं चार बीएस-6 माडल की बसें लौट आने से इस रूट के यात्रियों को राहत मिली है।

वहीं अब चुनाव ड्यूटी को लेकर पांचवें व छठवें चरण के मतदान को लेकर निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 17 बसों की डिमांड आई है। बुधवार को संभवता इन बसों को रवाना किया जाएगा। इसमें बीएस-4 बसें शामिल हैं। ऐसे में पड़ोसी जनपद व राजधानी लखनऊ से लेकर तमाम रूटों पर बसों का टोटा हो जाने की संभावना बढ़ी है। ऐसे में इन रूटों पर यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

हालांकि रोडवेज डिपो की ओर से बसों की कमी को पूरा करने के लिए रूटों पर बसों के फेरे बढ़ाने का फैसला लिया गया है। एआरएम (सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक) अपर्णा मीनाक्षी ने बताया कि 17 बसें पांचवे व छठवें चरण के मतदान की ड्यूटी में जा रही हैं। तो वहीं चुनाव ड्यूटी में गईं चार बीएस-6 बसें लौट आईं है। रूटों पर बसों की कमी न खले इसे लेकर फेरे बढ़ाने की तैयारी है।

सरकार पूरे हाईवे नेटवर्क की करेगी जीआईएस मैपिंग, जानें क्या है इस योजना का मकसद

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। भारत सरकार सभी नेशनल हाईवे की जीआईएस मैपिंग को पूरा करने की योजना बना रही है। इसका मकसद नेशनल हाईवे के बेहतर प्लानिंग, क्रियान्वयन और निगरानी और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए सभी राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले डेवलपरों के अधिकार क्षेत्र को चिह्नित करना है।

इस कदम से, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI), सीमा सड़क संगठन (BRO), राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (NHIDCL) और खुद मंत्रालय की सभी परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों को मई के आखिर से पहले राष्ट्रीय राजमार्ग डैशबोर्ड पर अपने अधिकार क्षेत्र को चिह्नित करने के लिए कहा है। ताकि भविष्य के संदर्भ और कार्यों में तेजी लाने के लिए क्षेत्रीय पृथक्करण के साथ हाईवे का पूरा जीआईएस डेटा उपलब्ध हो सके।

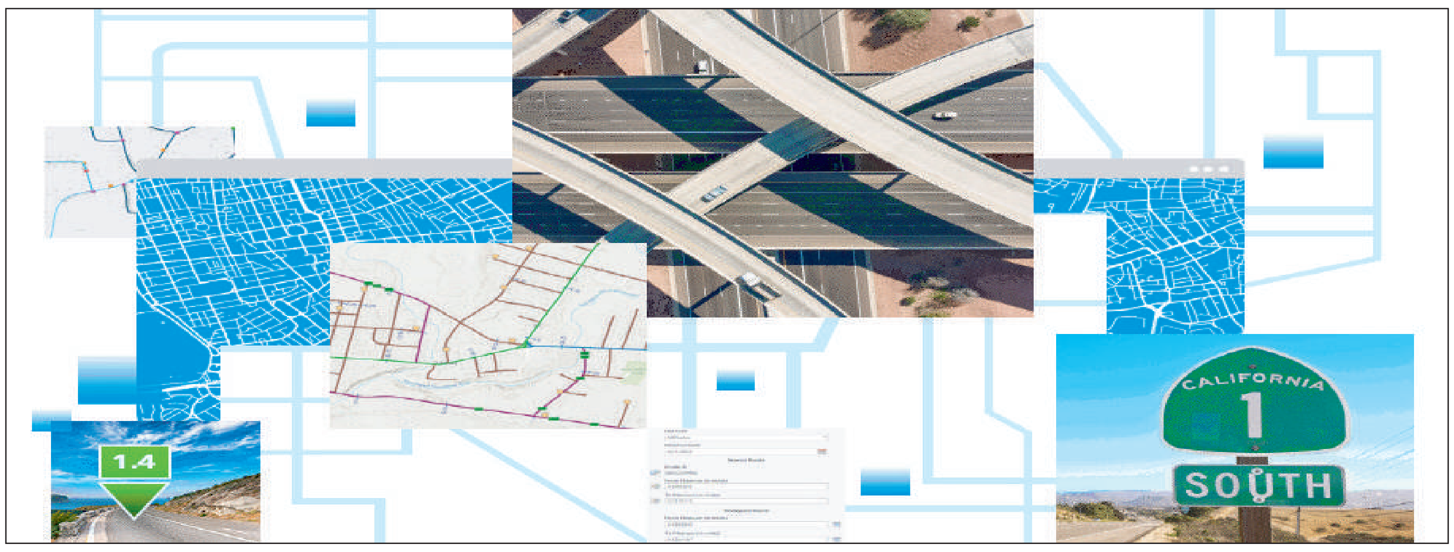

इस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर (एसओपी) (मानक संचालन प्रक्रिया) का मुख्य मकसद MoRTH द्वारा भारत में सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए जीआईएस-आधारित डेटा संग्रह को सुव्यवस्थित करना है। MoRTH के एक कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, एसओपी का लक्ष्य हर राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए उत्तरदायित्व क्षेत्र को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना है।

साथ ही, हाईवे सिस्टम से संबंधित विभिन्न संचार उद्देश्यों के लिए, नेटवर्क और डेटा विजुअलाइजेशन को परिभाषित करने के लिए मीडिया पोर्टल के जरिए एक जीआईएस-आधारित मैपिंग प्रणाली का उपयोग करना, डेटा सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक टीम द्वारा सत्यापन प्रक्रिया लागू करना और एकत्रित डेटा का उपयोग करना है।

इसके अलावा, एसओपी एक मानकीकृत डेटा संग्रह प्रक्रिया स्थापित करके कम्युनिकेशन फ्लो को बढ़ाते हुए सटीक और अपडेटेड जानकारी प्रदान करके पारदर्शिता में भी सुधार करेगा।

हर दिन 50 किलोमीटर सड़क निर्माण का कार्य करने के लिए, भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) टेक्नोलॉजी के सड़क निर्माण एजेंसियों की सहायता के लिए आने की भी उम्मीद है। क्योंकि यह संरेखण और राजमार्गों के मार्ग में किसी भी बाधा पर उचित जानकारी प्रदान करेगा।

गांधीनगर में भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना संस्थान (बीआईएसएजी-एन) ने नेशनल हाईवे के बड़े हिस्सों के लिए जीआईएस मैपिंग का काम किया है। और इस डेटा को मंत्रालय के लिए विभिन्न एजेंसियों की क्षेत्र इकाइयों द्वारा अपडेट और वेरिफाई किया गया है। एजेंसियों के अधिकार क्षेत्र के अंकन के साथ, जीआईएस मैपिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जिससे नए राजमार्ग संरेखणों में काम तेजी से शुरू हो सकेगा।

यंगिस्तान जिंदाबाद - सफलता की ऊंचाई: स्कूली बच्चों के लिए बास्केटबॉल क्यों आवश्यक है?

खेल के क्षेत्र में, बास्केटबॉल एक अद्वितीय कसरत के रूप में खड़ा है, खासकर स्कूली बच्चों के लिए। स्कूल के छात्रों ने युवाओं में ऊंचाई और सहनशक्ति बढ़ाने में बास्केटबॉल के महत्व पर प्रकाश डाला।

बास्केटबॉल महज़ एक खेल नहीं है; यह एक समग्र फिटनेस पैकेज है। बास्केटबॉल में शामिल निरंतर कूद और खिंचाव शरीर को लंबा करने में मदद करता है, प्राकृतिक विकास प्रक्रिया में सहायता करता है, जिससे ऊंचाई में वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त, खेल की तेज़ गति वाली प्रकृति उच्च सहनशक्ति स्तर की मांग करती है, जो समग्र फिटनेस के लिए सहनशक्ति विकास को बढ़ावा देती है। इसके अलावा, बास्केटबॉल आवश्यक जीवन कौशल विकसित करता है। यह टीम वर्क, संचार और नेतृत्व को बढ़ावा देता है, युवा दिमाग में अनुशासन और दृढ़ता पैदा करता है। कोर्ट पर बनी मित्रता कोर्ट के बाहर स्थायी मित्रता में बदल जाती है।

इसके अलावा, बास्केटबॉल ऊर्जा के लिए एक रचनात्मक आउटलेट प्रदान करता है, इसे एक उत्पादक गतिविधि में लगाता है, जिससे युवा शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहते हैं। यह शैक्षणिक दबावों के बीच मानसिक कल्याण को बढ़ावा देने के साथ-साथ एक शक्तिशाली तनाव निवारक के रूप में भी काम करता है।

स्कूल के छात्रों द्वारा बास्केटबॉल का समर्थन स्कूली बच्चों के समग्र विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। आइए इसे एक स्वस्थ, लम्बी और खुशहाल पीढ़ी के लिए तैयार करें !

"यह हमेशा माना जाता है कि जो फिट है वह हिट है, यंगिस्तान जिंदाबाद"

-अंकुर शरण

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020) , एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

आज की डिजिटल शुभकामनाएं ; डिजिटल युग में व्यक्तिगत संबंधों को अपनाना - अंकुर

आज हम जिस तेज़-तर्रार दुनिया में रहते हैं, जहाँ सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म सर्वोच्च हैं, डिजिटल कनेक्शन के समुद्र में खो जाना आसान है। जन्मदिन से लेकर अंत्येष्टि तक, हम खुद को लाइक, टिप्पणियों और इमोजी के माध्यम से जीवन के मील के पत्थर को पार करते हुए पाते हैं। लेकिन इस डिजिटल उन्माद के बीच, व्यक्तिगत संबंधों के मूल्य पर रुकना और विचार करना महत्वपूर्ण है, खासकर जीवन के सबसे कीमती अवसरों के दौरान।

इस तथ्य में एक निर्विवाद विडंबना है कि जहां हमें सोशल मीडिया पर जन्मदिन की शुभकामनाओं या संवेदनाओं की बाढ़ आ सकती है, वहीं फोन उठाने या आमने-सामने मिलने की कला गुमनामी में लुप्त होती जा रही है। फिर भी, इस सतह के नीचे भावनात्मक महत्व का एक गहरा भंडार है जो डिजिटल दायरे से परे है।

इसके बारे में सोचें - आखिरी बार कब आपने किसी की आवाज में गर्मजोशी सुनी थी जब उन्होंने आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं या व्यक्तिगत रूप से अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की थी? इन अंतःक्रियाओं में इतनी समृद्धि है कि इसे किसी स्क्रीन के माध्यम से दोहराया नहीं जा सकता।

सुविधा और दक्षता की तलाश में, हमें व्यक्तिगत संबंधों के गहरे प्रभाव को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। प्रत्येक जन्मदिन, सालगिरह, या मील का पत्थर न केवल उत्सव का अवसर है, बल्कि वास्तविक मानवीय संबंध का भी अवसर है - हमारे प्यार, कृतज्ञता और समर्थन को एक तरह से व्यक्त करने का मौका जो आभासी स्थान की सीमाओं से परे है।

इसलिए, जैसे-जैसे हम जीवन की यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, आइए इन व्यक्तिगत संबंधों को संजोना और पोषित करना याद रखें। आइए फोन उठाएं, एक पत्र लिखें, या इससे भी बेहतर, उन लोगों से मिलें जिन्हें हम प्रिय मानते हैं। आइए मानवीय संपर्क की सुंदरता और इससे हमारे जीवन में आने वाली भावनात्मक समृद्धि को अपनाएं।

ऐसा करने में, हम न केवल उन बंधनों को मजबूत करते हैं जो हमें एकजुट करते हैं बल्कि तेजी से डिजिटल होती दुनिया में वास्तविक, हार्दिक संबंधों के स्थायी मूल्य की भी पुष्टि करते हैं। तो, अगली बार जब आप खुद को सोशल मीडिया पर जन्मदिन की शुभकामनाओं या संवेदनाओं के सागर में स्क्रॉल करते हुए पाएं, तो व्यक्तिगत रूप से पहुंचने के लिए एक क्षण लें - क्योंकि अंत में, वास्तविक जुड़ाव के ये क्षण ही वास्तव में मायने रखते हैं।

संस्कारशाला : बचपन में मोबाइल की लत को समझना और उसका समाधान करना - प्रियंका श्रीवास्तव

बच्चों को स्क्रीन से चिपके हुए, मोबाइल उपकरणों या गैजेट्स में तल्लीन देखना असामान्य नहीं है। इन उपकरणों का आकर्षण निर्विवाद है, जो अंतहीन मनोरंजन और त्वरित संतुष्टि प्रदान करते हैं। हालाँकि, स्क्रीन पर निर्भरता की एक कीमत चुकानी पड़ती है, कई बच्चे कम उम्र से ही अपने मोबाइल के आदी हो जाते हैं।

इस लत की जड़ अक्सर मोबाइल उपकरणों की सुविधा और पहुंच में निहित होती है। गेम से लेकर सोशल मीडिया से लेकर शैक्षिक ऐप्स तक, हर बच्चे की रुचि के लिए कुछ न कुछ है, जिससे माता-पिता के लिए इलेक्ट्रॉनिक बेबीसिटर्स के रूप में इन उपकरणों पर भरोसा करना आसान हो जाता है। हालाँकि, जो चीज़ एक हानिरहित व्याकुलता के रूप में शुरू होती है वह तेजी से एक पूर्ण लत में बदल सकती है, क्योंकि बच्चे डिजिटल दुनिया से अलग होने के लिए संघर्ष करते हैं।

इसके अलावा, साथियों का दबाव और सामाजिक मानदंड बच्चों में मोबाइल की लत को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे-जैसे प्रौद्योगिकी दैनिक जीवन में अधिक एकीकृत होती जा रही है, बच्चे अपने साथियों के साथ बने रहने के लिए दबाव महसूस करते हैं, जिससे अत्यधिक स्क्रीन समय और सामाजिक संपर्क के लिए मोबाइल उपकरणों पर निर्भरता बढ़ जाती है।

इसके अलावा, मोबाइल ऐप्स और गेम की व्यसनी प्रकृति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ध्यान आकर्षित करने और उपयोगकर्ताओं को व्यस्त रखने के लिए डिज़ाइन किए गए, ये एप्लिकेशन अक्सर उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करने और उन्हें अधिक के लिए वापस लाने के लिए व्यवहार मनोविज्ञान से उधार ली गई रणनीतियों का उपयोग करते हैं। बच्चों के लिए, जिनका विकासशील मस्तिष्क विशेष रूप से ऐसी उत्तेजनाओं के प्रति संवेदनशील होता है, यह नशे की लत का कारण बन सकता है जिससे छुटकारा पाना मुश्किल होता है।

इस बढ़ती समस्या के समाधान के लिए, माता-पिता और देखभाल करने वालों को बच्चों के स्क्रीन समय को सीमित करने और स्वस्थ आदतों को प्रोत्साहित करने के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए। स्पष्ट सीमाएँ निर्धारित करने और घर में स्क्रीन-मुक्त क्षेत्र स्थापित करने से प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण बनाने में मदद मिल सकती है। इसके अतिरिक्त, बच्चों को बाहरी खेल, पढ़ना या रचनात्मक गतिविधियों जैसी वैकल्पिक गतिविधियों में शामिल करने से मोबाइल उपकरणों पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है।

मोबाइल की लत से निपटने में शिक्षा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बच्चों को संयम के महत्व और अत्यधिक स्क्रीन समय के संभावित जोखिमों के बारे में सिखाने से उन्हें प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में सूचित विकल्प चुनने में सशक्त बनाया जा सकता है।

जबकि मोबाइल डिवाइस कई लाभ प्रदान करते हैं, वे जोखिम भी पैदा करते हैं, खासकर जब बचपन की लत की बात आती है। इस घटना में योगदान देने वाले कारकों को समझकर और उन्हें संबोधित करने के लिए सक्रिय कदम उठाकर, माता-पिता और देखभाल करने वाले बच्चों को प्रौद्योगिकी के साथ एक स्वस्थ संबंध विकसित करने में मदद कर सकते हैं।

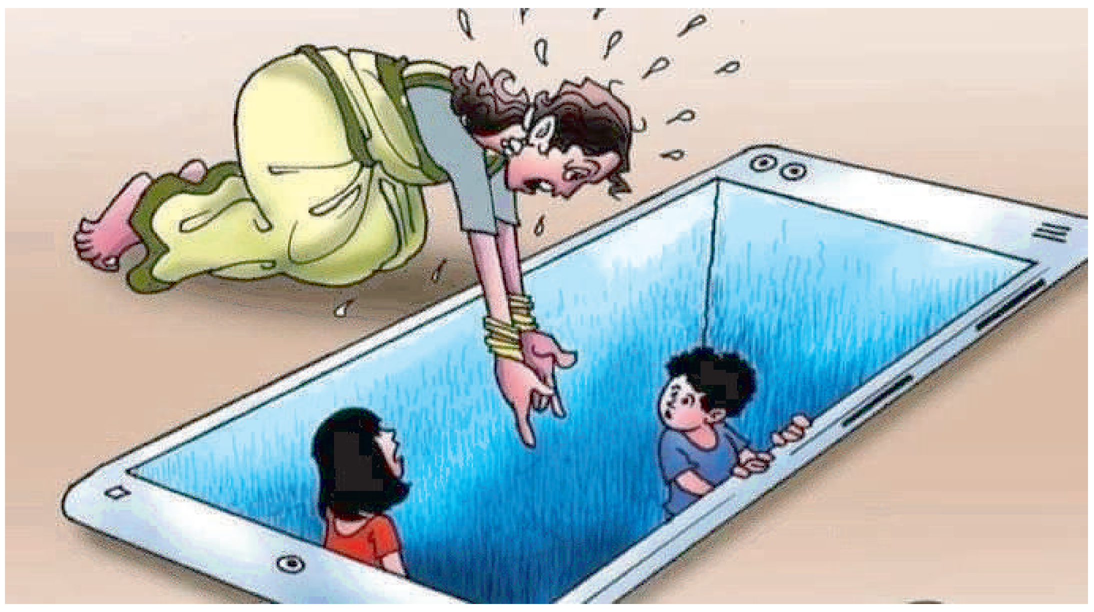

पर्यावरण पाठशाला : सहयोगात्मक प्रयासः @exl_service और गिव मी ट्रीज़ ने नोएडा में स्थिरता के बीज बोए -अंकुर

पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के एक ठोस प्रयास में, @exl_service और गिव मी ट्रीज़ (Give Me Trees) ने हाल ही में नोएडा के सेक्टर 150 में वृक्षारोपण अभियान के लिए हाथ मिलाया है। स्थिरता के प्रति आपसी प्रतिबद्धता से प्रेरित इस साझेदारी में स्वयंसेवकों और कर्मचारियों को एक ही उद्देश्य के साथ एकजुट होते देखा गयाः एक हरित कल के बीज बोना। शहरी विकास की पृष्ठभूमि के बीच, यह पहल स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को फिर से भरने और बहाल करने के सामूहिक संकल्प का प्रतीक है। जैसे ही पौधों को मिट्टी में अपना नया घर मिला, इस अधिनियम ने पर्यावरण चेतना और सामुदायिक जुड़ाव का एक गहरा संदेश प्रतिध्वनित किया। पेड़ लगाने के कार्य से परे, सहयोग सशक्तिकरण के व्यापक लोकाचार का प्रतीक है। कॉर्पोरेट संसाधनों और स्थानीय भागीदारी दोनों को जुटाकर, यह पहल न केवल जैव विविधता को बढ़ाती है बल्कि समुदायों को संरक्षण के सक्रिय एजेंट बनने के लिए भी सशक्त बनाती है। कॉर्पोरेट जिम्मेदारी और जमीनी स्तर की सक्रियता के बीच यह तालमेल सहयोगात्मक कार्रवाई की परिवर्तनकारी क्षमता को उजागर करता है। जैसे ही प्रत्येक पौधा जड़ पकड़ता है, यह एक स्थायी भविष्य की दिशा में एक ठोस कदम का प्रतिनिधित्व करता है - जहां साझेदारी पनपती है, पारिस्थितिकी तंत्र पनपता है और समुदाय समृद्ध होते हैं। @exl_service और गिव मी ट्रीज़ मिलकर एक हरित, अधिक हरीभरी दुनिया का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं।

आज की दुनिया में पर्यावरण संरक्षण और हरित क्रांति के लिए कई लोग अपने अनूठे पहल कर रहे हैं। भारत में कई ऐसे नायक ,संगठन हैं , जो अपने क्षेत्र में प्रतिष्ठित हैं और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हैं। ₹पर्यावरण पाठशाला₹ एक ऐसा पहल है जो इन हरियाली क्रांति के नायकों की कहानियों को साझा करने का माध्यम बनाता है। इसमें हम उनकी प्रेरणादायक कहानियों को साझा करते हैं, जो हमें पर्यावरण की दिशा में अग्रसर करने के लिए प्रेरित करती हैं।

आपके पास कोई कहानी है, तो हमारे साथ साझा करें और हमारे हरित क्रांति आंदोलन का हिस्सा बनें

indiangreenbuddy@gmail.com

श्रीराम जी की कथा का रसपान करके हम जीवन में आने वाले कष्टों को कर सकते हैं दूर

सुखी भारती

श्रीसती जी आश्चर्यचकित हैं, कि शंकर भगवान ने एक राजपुत्र को 'सच्चिदानंद' कहकर प्रणाम क्यों किया? वे तो एक वनवासी हैं। जो कि अपनी पत्नी के वियोग में व्याकुल होकर वन में यहाँ-वहाँ भटक रहे हैं। पूरी दुनिया शंकर जी को पूजती है।

हम हमारे छोटे से जीवन में, कैसे आने वाले कष्टों से बच पायें, कैसे उनका निवारण कर पायें, निश्चित ही इसका उपाय श्रीराम जी की कथा का रसपान करना ही है। कारण कि वैसे तो कर्मों के प्रभाव से बचना असंभव है, लेकिन अगर श्रीराम जी की कथा का अभेद्य कवच हमें मिल जाये, तो उसे काल द्वारा भेदना भी सर्वदा असंभव है।

श्रीसती जी को भी अपने जीवन में यह पावन अवसर प्राप्त हुआ था, कि वे श्रीराम जी की पुनीत कथा का रसपान करती। किंतु कुबुद्धि के दुष्प्रभाव में आकर, वे इस सुअवसर से वंचित रह जाती हैं। जिसका परिणाम यह होता है, वे श्रीसती जी, जिन्होंने भगवान शंकर जी को पति रुप में वरण करने के लिए, अपने समस्त सुखों व रिश्तों की तिलांजलि दी, आज उन्हीं, भगवान शंकर जी की बात पर उन्हें शंका हो रही है। कारण कि जब श्रीसती जी ने, भगवान शंकर जी को देखा, कि वे दोनों हाथ जोड़ कर, श्रीराम जी को प्रणाम कर रहे हैं, तो श्रीसती जी के मन में अनेकों प्रश्नों ने जन्म ले लिआ। वे देख रही हैं, कि शंकर भगवान ने वनवासी श्रीराम जी के दर्शन क्या किए, वे तो प्रेम भाव से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। कारण कि शंकर भगवान श्रीराम जी को प्रणाम कर वहाँ रुके नहीं, अपितु आगे बढ़ गये। पूरे रास्ते भगवान शंकर, श्रीराम जी की दिव्य लीलायों का ही गान कर रहे हैं-

'जय सच्चिदानंद जग पावन।
अस कहि चलेउ मनोज नसावन।।
चले जात सिव सती समेता।
पुनि पुनि पुलकत कृपानिकेता।।'

श्रीसती जी आश्चर्यचकित हैं, कि शंकर भगवान ने एक राजपुत्र को 'सच्चिदानंद' कहकर प्रणाम क्यों किया? वे तो एक वनवासी हैं। जो कि अपनी पत्नी के वियोग में व्याकुल होकर वन में यहाँ-वहाँ भटक रहे हैं। पूरी दुनिया शंकर जी को पूजती है। लेकिन वे ही किसी को पूजने लगें, और वह भी एक राजा के पुत्र को, तो यह बात मेरे गले नहीं उतरती-

'बिष्नु जो सुर हित नरतनु धारी।
सोउ सर्बग्य जथा त्रिपुरारी।।
खोजइ सो कि अग्य इव नारी।
ग्यानधाम श्रीपति असुरारी।।'

श्रीसती जी सोच में पड़ी हैं, कि अगर श्रीराम जी विष्णु जी के अवतार हैं, तो स्वाभाविक है, कि वे भी भगवान शंकर जी की भाँति ही सर्वज्ञ होंगे। उनसे भला संसार में क्या छुपा होगा? वे तो कण-कण की चाल से अवगत होंगे। फिर वे ज्ञान के भण्डार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु, क्या ऐसे अज्ञानीयों की भाँति अपनी स्त्री को खोजेंगे?

स्वधर्म संदेश : "एक प्यार का नगमा है। मौजों की रवानी है ।जिंदगी और कुछ भी नहीं आने जाने की कहानी है।"

मेरा तेरा अपना पराया ममता माया मोह लोभ अहंकार ने जीवन को नीरस बना दिया है। सामाजिक जीवन के वातावरण को आज का स्वार्थी समाज इतना दूषित बना दिया है कि इंसान सभी बात को जानने के बाद भी वही करता है, जो जीवन में नहीं करना चाहिए ।लोभ लालच स्वार्थ अपना पराया के चक्कर में इंसान वे सारे गलत गतिविधियों में जीवन का सुख और आनंद की खोज में सारा समय बेकार कर देता है। जिसकी जरूरत किसी भी काम में ज्यादा उलझने से नहीं होता है। जितना कि इंसान किसी काम में फंसकर जीवन को व्यर्थ गंवा देता है। जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन जरूरी है, पर धन प्राप्ति के चक्कर में जीवन मूल्यों को ही ताक पर रख देना कोई औचित्य पूर्ण गतिविधि नहीं हो सकती है।

आज देश और दुनिया के इंसानों की गतिविधियों को देखने के बाद काफी उदासी इसीलिए हाथ लगती है क्योंकि आज इंसान अपने जीवन के मूल्यों को खोकर सुख की प्राप्ति में भटकता फिरता है पर जीवन में सुख इसीलिए नहीं मिल पाता क्योंकि सुख का आधार तो संतोष है और पैसे से संतोष नहीं खरीदा जा सकता। संतोष मन के अंदर की पवित्र भाव को कहते हैं जो इंसान को लोभ लालच स्वार्थ अवसरवाद और अहंकार से कोसों दूर कर देता है। उस इंसान के अंदर किसी के प्रति बुड़े भाव की अवस्था नहीं रह जाती है। जो गलत है। उसे गलत कह कर हम उसमें बदलाव नहीं कर सकते। किसी को बदलने के लिए उसके अंदर की अच्छाइयों को आधार बनाकर उसके चरित्र निर्माण की गतिविधियों को ताकत दिया जा सकता है। समय को सही ढंग से जीना ही जीवन का आनंद है। जिसने अपने जीवन के समय का सही सदुपयोग किया। सकारात्मक उद्देश्यों की पूर्ति में लगाया। लक्ष्य को निर्धारित कर मानवीय चेतना के तहत ₹सर्वजन हिताय बहुजन सुखाय₹ की भावना से अपने जीवन में हर गतिविधियों को व्यवस्थित किया। उन्हीं लोगों का जीवन धन्य बना है। धन संपत्ति वैभव अहंकार पद प्रतिष्ठा के माध्यम से कभी किसी ने इंसानी जज्बातों की स्थापना के लिए जो जरूरी काम है। उसमें सफलता को नहीं प्राप्त किया है। त्याग तपस्या ईमानदारी सहिष्णुता और सहकारिता मानवीय जीवन का सबसे अमूल्य ताकत है ।जिसको पाकर जीवन धन्य बन जाता है।

जब देश के अंदर लोगों के भटकाव अराजकता अमानवीयता शोषण दोहन दमन झूठ फरेब लूट मार अवसरवादी आचरण की बल पर वर्चस्व की व्यवस्था बनाकर समाज में प्रभुत्व की जिस सामाजिक कामना को ताकत दे सकता है। जब सामाजिक जीवन में अराजक स्थिति और भेदभाव को बढ़ावा दिया जाता है तो निश्चित ही मानवीय भावनाओं का दोहन और क्षरण देश की स्वस्थ व्यवस्था का विरोध दिखाई देता है। इंसान स्वार्थ में इतना ज्यादा अंदर से खुद को सीमित कर लिया है। अपने भावना को इतना गलत बना लिया है कि वह कभी आत्मीय रूप से सुख और संतोष की अनुभूति कर ही नहीं सकता। यही व्यवस्था की वास्तविक सच्चाई है। व्यक्ति व्यवस्था को चलाता है पर दुर्भाग्य है कि व्यवस्था कुछ इस तरह की बन गई है कि व्यवस्था बदलाव के बिना मानवीय शक्ति को मजबूत करने की गतिविधियों को नहीं बदला जा सकता है। हर बदलाव में व्यक्तित्व का बहुत बड़ा महत्व होता है। हर काल में समाज में बदलाव के लिए ईश्वर ने महान विचारों को स्थापित करने के लिए किसी न किसी रूप में सकारात्मक शक्ति को बदलाव के लिए काम करने की प्रेरणा से देश और समाज में भेजता है। भारत में वर्तमान समय में बदलाव के लिए मुझे कुछ ईश्वरीय शक्ति के परादूभाव की अनुभूति होती है। देश की जनता अगर सकारात्मक सोच के तहत अपने भविष्य की रक्षा और विकास के लिए सही सोच विकसित करें तो निश्चित ही दैवीय शक्ति दिखाई दे सकता है और देश हित को ताकत मिलना संभव हो सकेगा।

डॉ राजू कुमार विद्यार्थी
सामाजिक राजनीतिक विचारक

दिल्ली में 15 मई को ग्रेजुएशन के लिए होने वाली सीयूईटी परीक्षा स्थगित, अब इस तारीख को होगा एग्जाम

CUET UG 2024 Exam Postponed नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए NTA) ने बुधवार 15 मई को स्नातक के लिए दिल्ली के केंद्रों में होने वाली कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी CUET) को स्थगित कर दिया है। मंगलवार देर शाम को इसकी अधिसूचना जारी की गई है। एनटीए की ओर से इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है। 15 मई को होने वाली परीक्षा देशभर में उसी समय पर होती रहेंगी।

नई दिल्ली। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए, NTA) ने बुधवार 15 मई (बुधवार) को स्नातक के लिए दिल्ली के केंद्रों में होने वाली कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी, CUET) को स्थगित कर दिया है। मंगलवार देर शाम को इसकी अधिसूचना जारी की गई है।

एनटीए की ओर से इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है। अधिसूचना में कहा गया है कि परीक्षा अब 29 मई को दिल्ली में होगी और उम्मीदवारों के लिए संशोधित प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। वहीं, दिल्ली के अलावा देशभर में होने वाली परीक्षा निर्धारित समय पर ही होगी। उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

ये हैं वो पेपर

एनटीए ने अधिसूचना में कहा है कि सभी संबंधित उम्मीदवारों को सूचित किया जा रहा है कि अपरिहार्य कारणों से टेस्टिंग पेपर स्थगित कर दिए गए हैं। ये पेपर रसायन विज्ञान-306, जीवविज्ञान-304, अंग्रेजी-101, और जनरल टेस्ट-501 हैं। यह टेस्ट पेपर 15 मई 2024 (बुधवार) को दिल्ली के केंद्रों में होने थे।

दिल्ली के बाहर शहरों में निर्धारित समय पर होगी परीक्षा

इसमें आगे कहा गया है कि 15 मई को होने वाली परीक्षा गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद और नोएडा सहित देश भर के सभी शहरों और विदेशों में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत ही आयोजित की जाएगी।

दिल्ली में अन्य तारीखों पर होने वाली परीक्षा होती रहेंगी

एनटीए ने कहा कि दिल्ली सहित सभी केंद्रों पर अन्य तिथियों (16, 17 और 18 मई) को निर्धारित परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएंगी। सिर्फ 15 मई को होने वाली परीक्षा की तिथि में बदलाव किया गया है।

स्वाति मालीवाल से बदसलूकी मामले में दिल्ली पुलिस को किसका इंतजार? यहां जानिए आगे क्या होगा...

परिवहन विशेष न्यूज

आप की राज्यसभा सदस्य एवं दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ सोमवार सुबह सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के अंदर मारपीट किए जाने का मामला धीरे-धीरे तूल पकड़ने लगा है। लेकिन उन्होंने इस मामले में अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं की है। पुलिस उनकी शिकायत का इंतजार कर रही है।

नई दिल्ली। आप की राज्यसभा सदस्य एवं दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal) के साथ सोमवार सुबह सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के अंदर मारपीट किए जाने का मामला धीरे-धीरे तूल पकड़ने लगा है। लेकिन, उन्होंने इस मामले में अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं की है। पुलिस उनकी शिकायत का इंतजार कर रही है।

हालांकि, आप नेता संजय सिंह ने मंगलवार को एक बयान में स्वाति से बदतमीजी व अभद्रता की बात कहकर इस घटना की पुष्टि कर दी है। इसके बाद पुलिस कार्रवाई को लेकर मंथन कर रही है।

पीसीआर कॉल पर क्या मिली शिकायत

सोमवार को मुख्यमंत्री आवास पहुंचीं स्वाति ने पीसीआर कॉल कर शिकायत की थी कि अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार ने उनकी बुरी तरह से पिटाई की और बदतमीजी भी की। वे मुख्यमंत्री आवास से निकलीं और सिविल लाइंस थाने पहुंच गईं।

स्वाति ने थानाध्यक्ष राजीव कुमार से मुलाकात कर मौखिक शिकायत की, उन्हें आपबीती बताई और मुकदमा दर्ज करने के लिए लिखित शिकायत देने की बात कहकर थाने से लौट भी गईं। तब से अब तक उन्होंने शिकायत नहीं दी है।

स्वाति मालीवाल ने नहीं किया कोई संपर्क

पुलिस अधिकारी का कहना है कि थाने से जाने के बाद स्वाति मालीवाल ने दोबारा कोई संपर्क नहीं किया है। अब तक लिखित शिकायत प्राप्त न होने पर महिला अपराध के इस संगीन मामले में पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही है। पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज करने के बाद ही पुलिस आगे की कार्रवाई कर सकती है।

पुलिस कई बार साध चुकी है संपर्क

सूत्रों के अनुसार, पुलिस सोमवार से अब तक स्वाति से कई बार संपर्क साध उन्हें मुकदमा दर्ज करने के लिए लिखित शिकायत देने का अनुरोध कर चुकी है, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। पहले पुलिस पीसीआर कॉल के आधार पर यह बात मानने को तैयार नहीं थी कि स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की भी गई अथवा नहीं। लेकिन, मंगलवार को आप के ही राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने मीडिया को जारी बयान में इसकी पुष्टि कर दी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के अंदर उनके निजी सचिव विभव कुमार ने स्वाति के साथ अभद्रता की।

इस बयान के बाद पुलिस का शक हकीकत में बदल गया। पुलिस को अब इस मसले पर कोई निर्णय लेना होगा। स्वाति मालीवाल, महिला अपराध के खिलाफ हमेशा से पुरजोर आवाज उठाती रहीं हैं। इसलिए माना जा रहा है कि खुद के साथ घटित घटना पर वह चुप्पी नहीं साधेंगी।

संजय सिंह ने अपने बयान में विभव कुमार पर कार्रवाई करने की बात कही है। दिल्ली पुलिस के पीछे के इतिहास को देखा जाए तो एक्स पर पोस्ट करने व आपत्तिजनक बयान के आधार पर पुलिस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नोटिस भेज पूछताछ करने उनके आवास पर पहुंच गई थी। इस मामले में पुलिस का क्या रुख रहेगा यह आने वाले समय में पता चलेगा।

ईडी ने कोर्ट में किया ऐलान पार्टी को बना रहे हैं आरोपी, मुश्किल में आम आदमी पार्टी

परिवहन विशेष न्यूज

एसडी सेठी। तिहाड जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए ईडी ने साफ कह दिया कि वह जल्द ही आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाने जा रही है।इसके लिए नया आरोप पत्र तैयार दायर किया जाएगा। कथित शराब घोटाले की जांच कर रही (प्रवर्तन निदेशालय) ईडी ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट मे वह ऐलान कर दिया ,जिसको लोकप्रियता कुछ महीनों से खूब अटकलें चल रही थी। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए ईडी ने साफ कह दिया कि वह जल्द ही आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाने जा रहे है।

जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में ईडी के वकील जोएब हुसैन ने कहा कि 'नए चार्जशीट में आम आदमी पार्टी को सह आरोपी बनाया जाएगा। जांच ऐजेंसी के वकील ने कहा कि आरोपी व्यक्तियों की ओर से आरोप पत्र तय करने की प्रकिया में देरी की कोशिशे की जा रही है।सिसोदिया के लिए मांगते हुए सिसौदिया के वकील ने कहा कि ईडी और सीबीआई अभी भी

लोगों की गिरफ्तारी कर रही है।और ट्रयाल के जल्द निष्कर्ष का सवाल ही नहीं है। दावे के मुताबिक यदि ईडी आम आदमी को आरोपी बनाती है तो यह पहली होगा। जानकारों का मानना है कि आरोपी बनाती है तो यह पहली बार होगा जब किसी राष्ट्रीय दल के खिलाफ पीएमएलए का केस दर्ज होगा। जानकारों का कहना है कि आरोपी बनाए जाने से आम आदमी पार्टी के खिलाफ मुसीबतों के नए दौर की शुरूआत हो सकती है। इसमें पार्टी की संपतिसे लेकर झाड़ निशान तक पर खतरा मंडरा सकता है।गौरतलब है कि एक दशक पहले भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के कोख से जन्मी पार्टी के मुखिया समेत कई नेता कथित शराब घोटाले में पहले ही जेल जा चुके है। पार्टी सुप्रीमों अरविंद केजरीवाल फिलहाल 21 दिन की अंतरिम जमानत पर बाहर निकले हैं। शीर्ष अदालत ने उन्हें लोकसभा चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने के लिए राहत दी है।

खाली दुकान का लिया सहारा और कर डाला खेल, गहनों की दुकान में किया छेद और...

उत्तरी दिल्ली के कोतवाली क्षेत्र में दरीबा कलां में चोरों ने बराबर की बंद पड़ी दुकान में घुसकर दीवार तोड़ आभूषण की दुकान में घुसकर चांदी की चोरी कर ली। कोतवाली पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी हैं। उत्तरी दिल्ली के डीसीपी मनोज कुमार मीणा ने बताया कि कोतवाली में सोमवार को चोरी के संबंध में एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई।

नई दिल्ली। उत्तरी दिल्ली के कोतवाली क्षेत्र में दरीबा कलां में चोरों ने बराबर की बंद पड़ी दुकान में घुसकर दीवार तोड़ आभूषण की दुकान में घुसकर चांदी की चोरी कर ली। कोतवाली पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी हैं।

उत्तरी दिल्ली के डीसीपी मनोज कुमार मीणा ने बताया कि कोतवाली में सोमवार को चोरी के संबंध में एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई। मौके पर पहुंची पुलिस टीम को शिकायतकर्ता ने बताया कि शनिवार रात करीब साढ़े आठ बजे वह अपनी दुकान सोनी चुन्नी लाल पोपट लाल ज्वैलर्स बंद कर घर चला गया।

दो दुकानों के बीच की दीवार तोड़ी

सोमवार को उसने अपने पिता के साथ अपनी दुकान खोली तो बगल में सालों से बंद पड़ी जर्जर हालत दुकान और उनकी दुकान के बीच की दीवार में छेद हुआ मिला। दुकान के सामान की जांच करने पर पता चला कि चांदी की कई वस्तुएं चोरी हो गईं।

दुकान में छेदकर की चोरी

आशंका है कि बंद दुकान के बोर्ड की जगह से कूदकर बराबर की दुकान की दीवार में छेदकर ज्वैलर्स की दुकान में घुस चोरी की गई। स्थानीय पुलिस के साथ ही क्राइम टीम और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर जांच की। आइपीसी की धारा 457/380 के तहत एफआइआर संख्या दर्ज कर जांच की जा रही है।

स्वाति मालीवाल संग बदसलूकी मामले में आप ने तोड़ी चुप्पी, केजरीवाल के निजी सचिव पर होगी कड़ी कार्रवाई

आम आदमी पार्टी (AAP) की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी के मामले में आप नेता संजय सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर स्वाति के साथ दुर्व्यवहार हुआ था और बदसलूकी सीएम केजरीवाल के पीए विभव कुमार द्वारा की गई। संजय सिंह ने प्रेस वार्ता में कहा कि स्वाति मालीवाल के साथ हुई घटना कल की है।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी के मामले में आप नेता संजय सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ दुर्व्यवहार हुआ था और बदसलूकी सीएम केजरीवाल के पीएस विभव कुमार द्वारा की गई। संजय सिंह ने प्रेस वार्ता में कहा कि स्वाति मालीवाल के साथ हुई घटना कल की है। स्वाति मालीवाल ने इस घटना की जानकारी दिल्ली पुलिस को दे दी है। यह एक निंदनीय घटना है। अरविंद केजरीवाल ने मामले का संज्ञान लिया है और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

हम स्वाति के साथ: प्रेस वार्ता कर कहा, सोमवार सुबह स्वाति मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने सीएम हाउस गई थीं, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थीं। उसी समय सीएम के पीएस विभव कुमार आए और उन्होंने उनके साथ बदतमीजी की। स्वाति ने 112 नंबर पर फोन कर पुलिस को सूचना दी। विभव के कृत्य की जितनी निंदा की जाए कम है। स्वाति ने महिलाओं और देश के लिए बहुत काम किए हैं, वह पार्टी की पुरानी व सीनियर लीडर हैं, हम सब उनके साथ हैं।

पुलिस आयुक्त ने घटना के बारे में क्या बताया? विशेष आयुक्त कानून एवं व्यवस्था रवींद्र सिंह यादव का कहना है कि सोमवार सुबह करीब 9:10 बजे स्वाति मालीवाल अपनी निजी कार से मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचीं। वह मुख्यमंत्री से मिलना चाहती थीं, लेकिन उनके आवास पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें मिलने से मना कर दिया।

किस समय कॉल पर क्या बात हुई: इस पर थोड़ी देर तक बहस होने के बाद स्वाति ने 9:31 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को फोन कर मुख्यमंत्री के निजी सचिव विभव कुमार पर मारपीट करने का आरोप लगा दिया। कमांड रूम से कॉल 9:34 पर उत्तरी जिला पुलिस के कंट्रोल रूम में ट्रांसफर कर दी गई। यहां 9.39 बजे पर कॉल की डीडी एंट्री हुई।

आईटीओ की सीआर बिल्डिंग में आग लगने से एक अधिकारी की मौत, दमकल ने सात लोगों को बचाया

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली में मंगलवार को इनकम टैक्स सीआर बिल्डिंग में आग लगने से एक व्यक्ति (46) की मौत हो गई। दमकल ने आग पर काबू पा लिया। आग दोपहर बाद लगभग तीन बजे थी। बिल्डिंग से कुल सात लोगों को बचाया गया है। जिसमें पांच पुरुष और दो महिलाएं हैं। अधिकारी ने बताया कि बिल्डिंग के अंदर आग लगने के कारण कार्यालय अधीक्षक के रूप में कार्यरत व्यक्ति बेहोश मिला था।

नई दिल्ली। दिल्ली में मंगलवार को इनकम टैक्स सीआर बिल्डिंग में आग लगने से एक व्यक्ति (46) की मौत हो गई। दमकल ने आग पर काबू पा लिया है। आग दोपहर बाद लगभग तीन बजे थी। बिल्डिंग से कुल सात लोगों को बचाया गया है। जिसमें पांच पुरुष और दो महिलाएं हैं।

दिल्ली अग्निशमक विभाग के अधिकारी ने बताया कि बिल्डिंग के अंदर आग लगने के कारण कार्यालय अधीक्षक के रूप में कार्यरत व्यक्ति बेहोश मिला था। बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया, जिसे मृत घोषित कर दिया।

दोपहर तीन बजे लगी ाग

आग पुराने पुलिस मुख्यालय के सामने स्थित इमारत में लगी है। जहां पुलिस बल की कुछ इकाइयां अभी भी रहती हैं। अग्निशमक विभाग ने बताया कि दोपहर 3:07 बजे इनकम टैक्स सीआर बिल्डिंग में आग लगने की सूचना मिली। सूचना के बाद तुरंत मौके पर दमकल की 21 गाड़ियां मौके पर भेजीं।

डीएफएस प्रमुख अतुल गर्ग ने कहा कि मुझे शाम 4 बजे सूचना मिली कि डीएफएस ने इमारत की तीसरी मंजिल से कुल सात लोगों (पांच पुरुषों और दो महिलाओं) को सुरक्षित बचाया है।

जैसे ही दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे, उन्होंने इमारत को खाली करा लिया। जहरीले धुएं के कारण हमें गैस मास्क का इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन इमारत में मौजूद सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। हमने मामले की आगे की जांच के लिए इलाके की स्थानीय पुलिस को सूचित कर दिया है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।

पेशेवर लापरवाही के लिए वकीलों पर मुकदमा नहीं हो सकता, पढ़ें पूरा फैसला

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक फैसले में कहा कि सेवाओं में कमी के लिए अधिवक्ताओं को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता। न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 का उद्देश्य और विषय केवल उपभोक्ताओं को अनुचित प्रथाओं एवं अनैतिक व्यावसायिक प्रथाओं से सुरक्षा प्रदान करना है। विधायिका का इरादा कभी भी व्यवसाय या इसके पेशेवरों को क़ानून के तहत शामिल करने का नहीं था। पीठ ने कहा कि हमने 'पेशे' को 'व्यवसाय' और 'व्यापार' से अलग किया है। हमने कहा है कि किसी पेशे के लिए एजुकेशन या साइंस की किसी ब्रांच में एडवांस एजुकेशन और ट्रेनिंग की जरूरत होगी। काम की प्रकृति अलग है, जिसमें शरीर के बजाय दिमाग पर ज्यादा जोर पड़ता है। किसी पेशेवर के साथ किसी व्यवसायी या व्यापारी की तरह समान व्यवहार नहीं किया जा सकता।₹ हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक वकील पर साधारणतया लापरवाही के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। इससे पहले 2007 में, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने फैसला सुनाया था कि अधिवक्ताओं द्वारा प्रदान की गई सेवाएं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे में आती हैं। अपील पर, सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2009 में पारित एक अंतरिम आदेश में, अपील के लंबित रहने के दौरान एनसीडीआरसी के फैसले के लागू होने पर रोक लगा दी थी।

बाइक सवार बदमाशों ने दूध कारोबारी के पैर में मारी गोली, रुपये के लेनदेन को लेकर चल रहा था विवाद

निठोरा गेट के निकट बाइक सवार दो बदमाशों ने सोमवार रात गाजियाबाद से दूध देकर आ रहे एक दूधिया को गोली मारी दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची लोनी कोतवाली पुलिस ने घायल को दिल्ली जीटीवी अस्पताल में भर्ती कराया है। जहां उपचार चल रहा है। हायक पुलिस आयुक्त सूर्य बली मौर्य ने बताया की रिपोर्ट लिख आरोपितों की तलाश की जा रही है।

लोनी। लोनी कोतवाली क्षेत्र चिरौडी रोड स्थित निठोरा गेट के निकट बाइक सवार दो बदमाशों ने सोमवार रात गाजियाबाद से दूध देकर आ रहे एक दूधिया को गोली मारी दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची लोनी कोतवाली पुलिस ने घायल को दिल्ली जीटीवी अस्पताल में भर्ती कराया है। जहां उपचार चल रहा है। पीड़ित की शिकायत लेकर मुकदमा लिख पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। सिरोली गांव के सतपाल (40) ने पुलिस को बताया की ढिकोली निवासो प्रशांत व रजत पुत्र नरेंद्र से मेरा भैंस के पैसों को लेकर लेन देन था। जिसके पैसे मैं दे चुका हूं, लेकिन दोनो भाई फिर भी पैसे मांग रहे थे। जिसकी कहासुनी हो गई थी। विवाद बढ़ने बाद आरोपित ने पैर गोली मार दी। सहायक पुलिस आयुक्त सूर्य बली मौर्य ने बताया की रिपोर्ट लिख आरोपितों की तलाश की जा रही है।

खौफनाक मंजर, बिखरी पड़ी लाशें... कार में फंसकर तड़पता रहा सचिन, समय पर नहीं पहुंचता अस्पताल तो चली जाती जान

परिवहन विशेष न्यूज

भईया... कहां हो तुम... मुझे बचाओ मेरा दम घुट रहा है। शायद हाथ–पैर की हड्डियां टूट गई हैं। जरा भी हिल नहीं पा रहा हूं। मुझे कार से बाहर निकालो। दुर्घटना के बाद कार में फंसा सचिन बार–बार बोलकर अपने भाई संदीप को मदद के लिए पुकार रहा था। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि संदीप के साथ उसके पांच अन्य दोस्त मौत की नींद सो चुके हैं।

हापुड़। भईया... कहां हो तुम... मुझे बचाओ,, मेरा दम घुट रहा है। शायद हाथ-पैर की हड्डियां टूट गई हैं। जरा भी हिल नहीं पा रहा हूं। मुझे कार से बाहर निकालो। दुर्घटना के बाद कार में फंसा सचिन बार-बार बोलकर अपने भाई संदीप को मदद के लिए पुकार रहा था। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि संदीप के साथ उसके पांच अन्य दोस्त मौत की नींद सो चुके हैं। काफी देर तक दर्द सह कर वह कार में फंसा रहा। इसी बीच पुलिस मौके पर पहुंची और कार सवार सभी लोगों को बाहर निकाला। इस दौरान सचिन बदहवास था। उसकी सांसें चलती देखकर पुलिस उसे अस्पताल ले गई।

हंसी-ठिठौली के बीच मची थी चीख पुकार

अस्पताल में होश में आने पर सचिन ने बताया कि कार में उसके भाई संदीप के अलावा उसके दोस्त रोहित सैनी, विपिन सोनी, अनूप सिंह, तरुण उर्फ निक्की जैन और राजकुमार जैन थे। अनूप कार चला रहा था। बाकी के लोग हंसी ठिठौली कर रहे थे। तभी अचानक कार डिवाइडर से टकराकर हवा में उछल गई। इस दौरान सभी में चींख-पुकार मच गई। इसी बीच किसी वाहन की टक्कर से सभी कार में फंस गए। सभी ने जिंदगी के लिए कुछ देर जद्दोजहद की थी लेकिन, उसके छोड़कर कोई भी नहीं बच सका।

दो भाईयों के प्रेम को लग गई नजर

स्वजन ने बताया कि संदीप के पिता रामकिशन का देहांत हो चुका है। वह माता राजकुमारी, भाई सचिन, पत्नी मधु, पुत्री विशु, पुत्र केशव व लड्डू के साथ रहता था। संदीप भाई सचिन के साथ कार वाशिंग का काम करता था। दोनों की बीच काफी प्यार था। मगर, दुनिया की नजर दोनों भाई के प्रेम को लग गई। तभी एक भाई मौत की नींद सो चुकी है। वहीं, दूसरा अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है।

अनूप की मां को कैसे बताएं कि बेटा नहीं रहा

अनुप अपने पिता करतार, माता कमलेश, भाई अक्षय, बहन मोनिका व प्रीति के साथ रहता था। मोर्चरी में अनूप के शव को देखकर स्वजन बिलख पड़े। रोते हुए स्वजन कह रहे थे कि अनूप की मां को कैसे बताएं कि बेटा नहीं रहा। वह तो यह सुनकर मर ही जाएगी। उधर, कुछ लोग स्वजन को शांत करने का प्रयास कर रहे थे।

तीन बच्चों के सिर पर नहीं रहा पिता का साया

विपिन के पिता लखमीचंद का देहांत हो गया है। वह माता कौशल्या, भाई रिखम सिंह, सुरेंद्र, मनोज, महिपाल, गोपाल, बहन अंकेश, पत्नी कोमल, पुत्री आशी, मल्लो व पुत्र वेदांत के साथ रहता था। उनकी मौत की खबर मिलते ही स्वजन हापुड़ पहुंचे। विपिन के शव को देखकर स्वजन कह रहे थे कि भगवान ने तीन मासूम बच्चों से पिता का साया छीन लिया है। अब कैसे उसकी पत्नी बच्चों की परवरिश करेगी।

दूधमुंही पुत्री को अकेला छोड़ गया तरुण

तरुण के पिता अनिल जैन का भी देहांत हो चुका है। वह माता सुमन जैन, पत्नी यशिका, भाई विकास, बहन नितू, निशा व एक साल की बेटी युविका के साथ रहता था। स्वजन ने बताया कि एक साल पहले जिस घर में बेटी की खुशियां मनाई गई थी। आज वहां मौत का सन्नाटा पसरा हुआ है। तरुण की पत्नी व अन्य स्वजन उसकी मौत के सदमे को सह नहीं पा रहे हैं।

परिवार पर मंडराए आर्थिक संकट के बादल

रोहित सैनी के पिता रामकिशन सैनी का देहांत हो गया है। काफी समय से रोहित कार चलाकर अपना व अपनी माता शांतिदेवी, भाई चंद्रपाल, पत्नी मनीषा और तीन पुत्री विधि, अर्धवी व सृष्टि का भरण पोषण करता आ रहा था। स्वजन ने बताया कि रोहित की मौत से एक तरफ जहां पूरे परिवार को गहरा सदमा लगा है। दूसरी तरफ परिवार पर आर्थिक संकट के बादल मंडराने लगे हैं।

अब कौन... बच्चों के खिलौने बनाएगा

राजकुमार जैन अपने पिता ओमपाल जैन, माता कुसुम जैन, भाई मुकेश, पत्नी इंदू जैन, पुत्री अंशिका व पुत्र ग्रंथ जैन के साथ रहता था। राजकुमार खिलौने बनाने का काम करता था। रोती-बिलखती मृतक की पत्नी ने कह रही थी कि हर सप्ताह वह बच्चों के लिए नए-नए खिलौने लाते थे। अब कौन बच्चों के लिए खिलौने लेकर आएगा। पति के बिना वह कैसे बच्चों का भरण पोषण कर सकेगी।

नहाने को लेकर विवाद में गला घोंटकर व्यक्ति की हत्या, नहर में फेंका शव

एक सप्ताह पहले राजेंद्रा पार्क थाना क्षेत्र के धनकोट नहर में नहाने को लेकर हुए विवाद में दो युवकों ने एक व्यक्ति की गला घोंटकर हत्या कर दी और नहर में ही शव फेंककर फरार हो गए। शुरुआत में पुलिस नहर में डूबने से व्यक्ति की मौत मानकर चल रही थी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में गला घोंटने की बात सामने आई और पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया।

गुरुग्राम। एक सप्ताह पहले राजेंद्रा पार्क थाना क्षेत्र के धनकोट नहर में नहाने को लेकर हुए विवाद में दो युवकों ने एक व्यक्ति की गला घोंटकर हत्या कर दी और नहर में ही शव फेंककर फरार हो गए। शुरुआत में पुलिस नहर में डूबने से व्यक्ति की मौत मानकर चल रही थी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में गला घोंटने की बात सामने आने पर पुलिस ने हत्या की धाराओं में केस दर्ज कर सोमवार रात दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया।

एसीपी वेस्ट शिव अर्चन शर्मा ने मंगलवार को बताया कि सात मई को धनकोट पुलिस चौकी को धनकोट नहर में एक व्यक्ति के शव पड़े होने की जानकारी मिली थी। पुलिस टीम ने शव को नहर से निकाला।

आंखें और होठों पर निशान

व्यक्ति की आंखों व होठों को पानी में रहने वाले जीवों द्वारा खाया होना प्रतीत हो रहा था। पहचान न होने पर पुलिस की सीन ऑफ क्राइम, एफएसएल की टीमों ने घनटास्थल पर निरीक्षण करने के बाद शव को पोस्टमॉर्टम हाउस में रखवा दिया गया।

शव की हुई पहचान

पुलिस जांच के दौरान मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर निवासी अनिल कुमार ने शव की पहचान बड़े भाई इंद्र साहनी (45) के रूप में की। बताया कि इंद्र साहनी फिलहाल यहां धनकोट गांव में परिवार के साथ किराये से रहते थे और निजी कंपनी में काम करते थे। शुरुआत में पुलिस इनकी मौत नहर में डूबने से होनी मान रही थी।

घोंटा गया था गला

इसके बाद पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में पता चला कि इंद्र साहनी का गला घोंटा गया। इस पर थाना पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। धनकोट चौकी प्रभारी सब इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार की टीमन ने आसपास के लोगों से पूछताछ और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर आरोपितों की पहचान की।

इसके बाद कार्रवाई करते हुए सोमवार को दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। इनकी पहचान गुरुग्राम के सेक्टर चार निवासी सहदेव चड्ढा व सूरत नगर निवासी दिनेश के रूप में की गई। सहदेव को सेक्टर 4 से और दिनेश को उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर के गांव छीतुनी से पकड़ा गया।

नहाने के लिए बीच नहर में जाने को लेकर हुआ था विवाद

पुलिस पूछताछ में पता चला कि दिनेश व सहदेव दोस्त हैं। छह मई ये दोनों धनकोट रोड वाली नहर में नहा रहे थे। इस दौरान इनकी मुलाकात इंद्र साहनी से हुई। सहदेव को तैरना नहीं आता था। इंद्र व दिनेश तैरना जानते थे। सहदेव नहर के किनारे पर नहा रहा था। इंद्र ने सहदेव को जबरदस्ती नहर के अंदर ले जाने के लिए कहा तो सहदेव ने मना कर दिया। इसी बात पर दोनों में कहासुनी हो गई।

इसके बाद सहदेव के साथी दिनेश ने इंद्र साहनी की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी। शव को नहर में ही फेंककर दोनों आरोपित रामवृक्ष की कार मारुति स्विफ्ट में सवार होकर फरार हो गए। पुलिस टीम ने दोनों आरोपितों को तीन दिन के रिमांड पर लिया है। उनके पास से एक कार, दो मोबाइल फोन व एक रस्सी बरामद की गई है।

अब गंगनहर घाट पर डुबकी नहीं लगा सकेंगे लोग, प्रशासन ने इस वजह से लगाई रोक

तपती गर्मी से राहत पाने के लिए गंगनहर घाट पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग नहाने के लिए आते हैं। बहुत से लोग नहाने के दौरान रोमांच पाने के लिए अपनी सुरक्षा को दरकिनार करके गहरे पानी में चले जाते हैं और हादसों का शिकार हो जाते हैं। हाल में इसी तरह छह लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।

मुरादनगर। हाल के दिनों में गंगनहर घाट पर एक के बाद हुए हादसों के बारे में दैनिक जागरण में खबर प्रकाशित होने पर पुलिस प्रशासन हरकत में आया है।

प्रशासन ने गंगनहर घाट पर नहाने को लेकर अस्थाई तौर से रोक लगा दी है। अगला आदेश मिलने तक रोक प्रभावी रहेगी।

अधिकारियों का कहना है कि नहर घाट पर आदेश की अवहेलना करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। इसके लिए घाट पर अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है।

गर्मी से राहत पाने को हजारों लोग रोज नहाने आते हैं

तपती गर्मी से राहत पाने के लिए गंगनहर घाट पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग नहाने के लिए आते हैं। बहुत से लोग नहाने के दौरान रोमांच पाने के लिए अपनी सुरक्षा को दरकिनार करके गहरे पानी में चले जाते हैं और हादसों का शिकार हो जाते हैं।

हाल में इसी तरह छह लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके अलावा प्रतिदिन कई लोगों को गोताखोर डूबने से बचाते हैं। इन हादसों की ओर पुलिस प्रशासन का ध्यान खींचने के लिए सोमवार को दैनिक जागरण में खबर प्रकाशित की गई। खबर लगने के बाद ही पुलिस प्रशासन त्वरित रूप से सक्रिय हुआ।

कार्रवाई करते हुए गंगनहर घाट पर नहाने को लेकर अस्थाई रोक लगा दी गई है। अब कोई भी व्यक्ति घाट पर नहा नहीं सकेगा।

हालांकि मंदिर में पूजा करने को लेकर किसी प्रकार की मनाही नहीं हैं। घाट स्थित शनि मंदिर के पुजारी मुकेश गोस्वामी का कहना है कि कुछ लोगों की लापरवाही के कारण गंगनहर घाट की छवि नकारात्मक तरीके से प्रभावित हो रही है। इसलिए नहर में नहाने पर रोक लगाकर प्रशासन ने सही निर्णय लिया है।

गंग नहर में नहाने के दौरान हुए हादसों की संख्या को देखते हुए रोक लगाई गई। आदेश की अवहेलना करने पर वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

-नरेश कुमार एसीपी, मसूरी

धर्म आधारित जनसंख्या का बढ़ता असंतुलन

18वीं लोकसभा के चुनावों की गहमा–गहमी के बीच एक ऐसी रिपोर्ट आई है, जिसे देश पहले से ही जानता था पर आधिकारिक तौर पर मोहर अब लगी है। पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ई.ए.सी.पी.एम.) द्वारा जारी 'धार्मिक अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी– एक...

18वीं लोकसभा के चुनावों की गहमा-गहमी के बीच एक ऐसी रिपोर्ट आई है, जिसे देश पहले से ही जानता था पर आधिकारिक तौर पर मोहर अब लगी है। पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ई.ए.सी.पी.एम.) द्वारा जारी 'धार्मिक अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी- एक क्रॉस कंट्री विश्लेषण (1950-2015)' शीर्षक से एक अध्ययन से पता चला है कि भारत में बहुसंख्यकों (हिंदुओं) की जनसंख्या हिस्सेदारी में गिरावट आई है।

अध्ययन में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि भारत में 1950 और 2015 के बीच बहुसंख्यक ड्ढषहदू आबादी की हिस्सेदारी 1950 में 84.68 प्रतिशत से घटकर 2015 में 78.06 प्रतिशत हो गई है, अर्थात इसमें 7.82 प्रतिशत की कमी आई है जबकि इसी अवधि (65 वर्ष) में मुसलमानों की हिस्सेदारी 9.84 प्रतिशत से बढ़कर 14.09 प्रतिशत हो गई है अर्थात 43.15 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि। इसी अवधि में ईसाइयों में 5.38 प्रतिशत की वृद्धि, सिखों में 6.58 प्रतिशत की और बौद्धों में मामूली वृद्धि देखी गई, जबकि जैन और पारसियों की संख्या में कमी देखी गई।

आजादी के समय देश का धर्म के आधार पर विभाजन हुआ - मुसलमानों और सैक्युलरों के बीच क्योंकि जहां पाकिस्तान केवल मुसलमानों के लिए बना, वहीं हिन्दुस्तान सभी धर्मों और सम्प्रदायों को साथ लेकर चलने वाला देश बन गया। जहां पाकिस्तान से चुन-चुन कर हिन्दुओं को भेजा गया या मार दिया गया, वहीं हिंदुस्तान में बड़ी संख्या में मुसलमान रह गए, जिनको समानता के साथ देश का नागरिक बने रहने का अधिकार मिला। कालखंड में इनकी संख्या बढ़ती गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भारत सैक्युलर है और यहां के बहुसंख्यक हिंदू सैक्युलर हैं। यही वजह है कि यहां और धर्मों तथा सम्प्रदायों को मानने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। शोर के विपरीत, इस रिपोर्ट के विश्लेषण से पता चलता है कि अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित हैं, बल्कि वास्तव में भारत में फल-फूल रहे हैं।

पर इस रिपोर्ट का एक दूसरा भी पहलू है। वह यह कि जैसे-जैसे हिन्दुओं की संख्या घटेगी, देश में सैक्युलरिज्म की अवधारणा पर चोट पहुंचेगी। हाल के दिनों में यह स्पष्टता से देखने में आया है। जहां-जहां हिन्दू अल्पसंख्यक हुए हैं, वहां इनटॉलरैंस बढने, शरिया लागू करने की मांग उभर कर आ रही है। देश के अनेक राज्यों और जिलों में जहां-जहां हिन्दू अल्पसंख्यक हुए हैं, वहां हिन्दुओं के धार्मिक जलूसों पर पथराव, हिंदू मान्यताओं का विरोध आदि शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल और केरल इसके मुख्य उदाहरण हैं।

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, देश के 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हिन्दू अल्पसंख्यक हो गए हैं (ये हैं- लद्दाख, जम्मू - कश्मीर, लक्षद्वीप, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, और अरुणाचल प्रदेश)। कुछ लोग पंजाब का भी नाम लेते हैं, पर वहां के बहुसंख्यक सिख हिन्दुओं का ही बृहत्तर हिस्सा हैं। इसके अलावा देश में ऐसे कई राज्य हैं, जहां हिन्दुओं की जनसंख्या तेजी से घट रही है और मुस्लिम जनसंख्या बढ़ रही है, जैसे कि पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तराखंड, जहां पर 2001 से 2011 के दशक में ही यह वृद्धि 2 प्रतिशत की थी। 2011 के बाद निस्संदेह यह संख्या बढ़ ही रही है।

इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वीकली में छपी एक रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार, केवल प्रदेशों में ही नहीं, देश के अनेकों जिलों में जनसंख्या का असंतुलन चिंताजनक तरीके से बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, देश के 458 जिलों में 2001 से 2011 के बीच मुस्लिम आबादी की वृद्धि 24.4 प्रतिशत की थी। कई जिले तो ऐसे हैं, जो पूरी तरह से मुस्लिम बहुल हो गए हैं। उदाहरण के तौर पर बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी है। यहां पर 66.8 प्रतिशत और इसके बाद नंबर आता है मालदा जिले का, जहां 51.27 प्रतिशत मुस्लिम आबादी है।

> “ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वीकली में छपी एक रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार, केवल प्रदेशों में ही नहीं, देश के अनेकों जिलों में जनसंख्या का असंतुलन चिंताजनक तरीके से बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, देश के 458 जिलों में 2001 से 2011 के बीच मुस्लिम आबादी की वृद्धि 24 .4 प्रतिशत की थी। कई जिले तो ऐसे हैं, जो पूरी तरह से मुस्लिम बहुल हो गए हैं। उदाहरण के तौर पर बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी है।

दरअसल मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या दर वोटबैंक की राजनीति का परिणाम है। कांग्रेस और तृणमूल तथा समाजवादी पार्टी सरीखे कई क्षेत्रीय दलों ने मुसलमानों को एक वोटबैंक की तरह इस्तेमाल किया है। कांग्रेस ने तो आजादी के समय से ही सत्ता पर पकड़ बनाए रखने के लिए मुस्लिम कार्ड खेला है। याद कीजिए, यह कांग्रेस ही थी, जो सत्ता के लिए धर्म के आधार पर देश का विभाजन करने को तैयार हो गई थी और यह वही कांग्रेस थी, जो एक ओर तो हिन्दुओं से 'हम दो, हमारे दो' का आह्वान करती रही, वहीं दूसरी ओर आज मुसलमानों के लिए 'जितनी आबादी, उतना हक' जैसे नारे देती है।

पश्चिम बंगाल में तो राजनीतिक लाभ और वोटों की चाह में जनसंख्या विद्रूपता अपने चरम पर है। वहां पर सत्तारूढ़ तृणमूल पर वोट बैंक के लिए बंगलादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देकर मुस्लिम जनसंख्या बढ़ाने का आरोप है। बंगाल सरकार की शह पर घुसपैठियों ने कथित तौर पर वोटर कार्ड से लेकर राशन, आधार कार्ड व पासपोर्ट जैसे दस्तावेज तक बना लिए हैं, जिससे मुस्लिम संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो चुनाव में अहम रोल निभाते हैं। आज पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट बड़ा फैक्टर बन गया है। ये लोकसभा की 42 में से 13 सीटों और विधानसभा की 294 में से करीब 100 सीटों पर हार-जीत करते हैं। बंगलादेश की सीमा से लगने वाले जिलों उत्तर दिनाजपुर में 49.92 प्रतिशत, बीरभूम में 37.06 प्रतिशत, दक्षिण 24 परगना में 35.57 प्रतिशत और उत्तर 24 परगना में 30 प्रतिशत मुस्लिम आबादी है, जो तृणमूल का वोट बैंक बन गई है। सी.एस.डी.एस.-लोकनीति पोस्ट पोल विश्लेषण के अनुसार, 2021 के चुनावों में 10 में से लगभग 8 मुसलमानों ने टी.एम.सी. को वोट दिया था, जो उसकी जीत का कारण बना।

आज भारत को एक व्यापक जनसंख्या नीति की जरूरत है। धर्म आधारित जनसंख्या असंतुलन को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। जनसंख्या का यह 'असंतुलन' ही अंत में भौगोलिक सीमा में बदलाव का कारक होता है, यह हम 1947 में देख चुके हैं जब देश का विभाजन जनसंख्या के 'असंतुलन' के कारण ही हुआ था। दुनिया में भी जनसंख्या 'असंतुलन' से हुए बदलावों के कई उदाहरण हैं जैसे कि ईस्ट तिमोर, दक्षिण सूडान और कोसोवो आदि जनसंख्या में असंतुलन के कारण ही नए देश बने हैं। लेबनान जैसे अति समृद्ध देश जनसंख्या असंतुलन के कारण तबाह हो गए।

समय आ गया है कि केंद्र में आने वाली एन.डी.ए. की सरकार कुछ सख्त फैसले ले और देश में जनसंख्या नियंत्रण, समान अचार संहिता जैसे कानून लाए। इससे आबादी बढ़ा कर राजनीतिक सत्ता हासिल करने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी। जनसंख्या नियंत्रित होने से देश के हर नागरिक, चाहे वह किसी मजहब को मानने वाला हो, के कल्याण के लिए देश के संसाधनों के सम्यक उपयोग का रास्ता प्रशस्त होगा।

-श्याम जाजू (पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भाजपा)

जल्द लॉन्च हो सकती हैं ये 4 नई हाइब्रिड कारें, मारुति से टोयोटा तक लिस्ट में शामिल

पॉपुलर मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा और टोयोटा अर्बन क्रूजर हायराइडर के 7-सीटर संस्करण के 2025 की पहली छमाही में आने की उम्मीद है। हाल के महीनों में टोयोटा फॉर्च्यूनर के माइल्ड-हाइब्रिड संस्करण को इसके हाइलेक्स एमएचईवी समकक्ष के साथ वैश्विक स्तर पर पेश किया गया है। इसके अलावा अपडेटेड मारुति सुजुकी फ्रोंक्स कथित तौर पर अगले साल किसी समय लॉन्च होगी।

नई दिल्ली। इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिक कारों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके साथ ही कई कार ब्रांड तत्काल वैकल्पिक समाधान के रूप में हाइब्रिड वाहनों पर विचार कर रहे हैं।

मारुति सुजुकी और टोयोटा अपने ईवी लाइनअप के साथ-साथ हाइब्रिड पावरट्रेन के विकास पर ध्यान केंद्रित करने वालों में सबसे आगे हैं। आइए, अपकमिंग हाइब्रिड कारों के बारे में जान लेते हैं। लिस्ट में केवल इन दोनों जापानी कंपनियों की गाड़िया हैं।

7-Seater Grand Vitara और Toyota Hyryder

पॉपुलर मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा और टोयोटा अर्बन क्रूजर हायराइडर के 7-सीटर संस्करण के 2025 की पहली छमाही में आने की उम्मीद है। ये मॉडल अपने 5-सीटर समकक्षों की तुलना में कॉस्मेटिक अपडेट के साथ आएंगे। दोनों मॉडल 1.5 लीटर माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल और 1.5 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन के बीच विकल्प पेश करेंगे।

Toyota Fortuner MHEV और Hilux MHEV

हाल के महीनों में टोयोटा फॉर्च्यूनर के माइल्ड-हाइब्रिड संस्करण को इसके हाइलेक्स एमएचईवी समकक्ष के साथ वैश्विक स्तर पर पेश किया गया है। हम इस साल के अंत में या 2025 में फॉर्च्यूनर एमएचईवी के आगमन की उम्मीद करते हैं और हाइलेक्स एमएचईवी भी इस दौरान लाइनअप में शामिल हो सकता है।

घरेलू बाजार में ये टाटा सफारी, हुंडई अलकजार, एमजी हेक्टर प्लस, 7-सीटर सिट्रोएन सी3 एयरक्रॉस और महिंद्रा एक्सयूवी700 जैसी एसयूवी को टक्कर देंगी।

Maruti Suzuki Fronx Facelift

अपडेटेड मारुति सुजुकी फ्रोंक्स कथित तौर पर अगले साल किसी समय लॉन्च होगी। अपनी शुरुआत के बाद से इस कॉम्पैक्ट एसयूवी कूप ने अपने प्राइस प्वाइंट और वाइड रेंज के कारण ग्राहकों के बीच महत्वपूर्ण रुचि पैदा की है। मिड-लाइफ अपडेट होने के कारण, इसमें केवल मामूली एक्सटीरियर और इंटीरियर अपडेट किए जाएंगे।

गर्मियों में इन 5 तरीकों से रखें अपने हेलमेट का ख्याल, नहीं होगी बदबू और वेंटिलेशन वाली दिक्कत

अपने हेलमेट को नियमित रूप से साफ करने की आदत बनाएं। अपने हेलमेट के वेंट से किसी भी जमा हुए मलबे धूल या कीड़ों को हटा दें। गंदगी हटाने और उचित वायु प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए मुलायम ब्रश या कंप्रेस्ड एयर का उपयोग करें। अगर आपके हेलमेट से बदबू आती है तो आप हेलमेट डिओडोराइजर का उपयोग कर सकते हैं।

नई दिल्ली। दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए हेलमेट बेहद महत्वपूर्ण हैं। बाइक हेलमेट को मेंटेनेंस के साथ-साथ नीट एंड क्लीन रखना बहुत जरूरी है। गर्मियों में अधिक पसीना आता है, तो ऐसे में हेलमेट का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आइए, बाइक हेलमेट को साफ और फ्रेश रखने के लिए जरूरी टिप्स जान लेते हैं।

नियमित सफाई

अपने हेलमेट को नियमित रूप से साफ करने की आदत बनाएं। खासकर लंबी सवारी के बाद या जब यह स्पष्ट रूप से गंदा हो जाए, तो इसे अंदर और बाहर ढंग से साफ करें। हेलमेट को मुलायम कपड़े या स्पंज से धीरे से रगड़ कर साफ करें।

वेंटिलेशन

अपने हेलमेट के वेंट से किसी भी जमा हुए मलबे, धूल या कीड़ों को हटा दें। गंदगी हटाने और उचित वायु प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए मुलायम ब्रश या कंप्रेस्ड एयर का उपयोग करें। इससे हेलमेट में वेंटिलेशन बढ़ेगा और दुर्गंध भी नहीं होगी।

स्वेट मैनेजमेंट

गर्मी के मौसम में सवारी करते समय पसीना आपके हेलमेट के अंदर जमा हो सकता है। पसीने को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए अपने बालों को ढकने के लिए टोपी या रूमाल का उपयोग करें।

सन प्रोटेक्शन

सीधे सूरज की रोशनी के लंबे समय तक संपर्क में रहने से समय के साथ हेलमेट के मैटेरियल में जल्दी खराबी हो सकती है। उपयोग में न होने पर इसे अपनी मोटरसाइकिल की सीट या किसी गर्म सतह पर छोड़ने से बचें। राइड पूरी होने के बाद हेलमेट को छांव में रखें।

ओडोर कंट्रोल

अगर आपके हेलमेट से बदबू आती है, तो आप हेलमेट डिओडोराइजर का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जब हेलमेट उपयोग में न हो, तो इसके अंदर बेकिंग सोडा या एक्टिव चारकोल जैसी चीजें रखकर गंध को कम किया जा सकता है।

रॉयल इनफील्ड ने क्लासिक 650 का कराया ट्रेडमार्क, जल्द लॉन्च हो सकती है सबसे किफायती 650 सीसी ट्विन

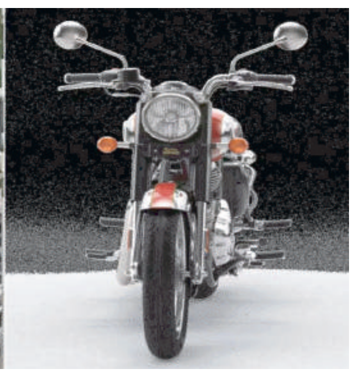

Royal Enfield कई नई मोटरसाइकिलों पर काम कर रही है जो निकट भविष्य में लॉन्च होंगी। मोटरसाइकिल का नाम क्लासिक 650 ट्विन होगा क्योंकि निर्माता ने इसके लिए एक नया नेमप्लेट ट्रेडमार्क दायर किया है। उम्मीद की जा सकती है कि रॉयल एनफील्ड Classic 650 Twinआने वाले महीनों में लॉन्च किया जाएगा। आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं।

नई दिल्ली। प्रीमियम दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Royal Enfield कई नई मोटरसाइकिलों पर काम कर रही है, जो निकट भविष्य में लॉन्च होंगी। ब्रांड का सबसे हालिया लॉन्च Shotgun 650 था, जो 650 सीसी लाइनअप में शामिल होने वाली चौथी मोटरसाइकिल है।

Royal Enfield Classic 650 कब होगी एंट्री

हम पहले से ही जानते हैं कि ब्रांड दो अन्य 650 सीसी मोटरसाइकिलों पर भी काम कर रहा है, जिन्हें जल्द ही भारतीय बाजार में लॉन्च किया जाएगा। उनमें से एक क्लासिक 650 होगी, जो निर्माता की लाइनअप में सबसे किफायती मोटरसाइकिल होगी।

मोटरसाइकिल का नाम ₹क्लासिक 650 ट्विन₹ होगा, क्योंकि निर्माता ने इसके लिए एक नया नेमप्लेट ट्रेडमार्क दायर किया है। उम्मीद की जा सकती है कि रॉयल एनफील्ड Classic 650 Twinआने वाले महीनों में लॉन्च किया जाएगा।

संभावित डिजाइन

पिछले स्पाई शॉट्स से पुष्टि हुई है कि स्टाइलिंग मौजूदा क्लासिक 350 के समान होगी, लेकिन आयाम बड़े होंगे क्योंकि मोटरसाइकिल शॉटगन 650 के प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी। हालांकि, मोटरसाइकिल को और अधिक किफायती बनाने के लिए इसमें कई बदलाव होंगे। उदाहरण के लिए, इसके फ्रंट में टेलिस्कोपिक फोर्क्स और रियर में ट्विन शॉक एब्जॉर्बर का इस्तेमाल किया गया है।

इसके हेडलैंप वही एलईडी यूनिट हैं, जिसे हमने नई रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिलों पर देखा है। हालांकि, हेडलैंप के ऊपर एक छोटा सा कवर है जिसे हमने 350 सीसी मोटरसाइकिलों और हैलोजन पायलट लैंप पर भी देखा है।

शॉटगन 650 का एग्जॉस्ट समान दिखता है लेकिन इसे ब्लैक आउट करने के बजाय क्रोम में तैयार किया गया है। यही बात इंजन के लिए भी है। काले पाउडर-लेपित आवरण को क्रोम से बदल दिया गया है। ऐसा लगता है कि फेंडर सुपर मीटियर 650 के साथ साझा किए गए हैं।

किआ कैरेंस फेसलिफ्ट टेस्टिंग के दौरान आई नजर, इन बदलावों के साथ जल्द मार सकती है एंट्री

परिवहन विशेष न्यूज

किआ कैरेंस एमपीवी को टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है। स्पाई शॉट्स इसके फेसलिफ्टेड वर्जन के आगे और पीछे के हिस्सों में महत्वपूर्ण बदलावों की एक झलक प्रदान करते हैं। उम्मीद है कि फेसलिफ्टेड कैरेंस में मौजूदा मॉडल का लेआउट बरकरार रहेगा जो 6 और 7-सीट कॉन्फिगरेशन की पेशकश करेगा। कैरेंस फेसलिफ्ट को वर्तमान में 1.5-लीटर एनए पेट्रोल इंजन 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन और 1.5-लीटर डीजल इंजन दिया गया है।

नई दिल्ली। Kia Carens MPV को मिड-साइकिल अपडेट मिलने वाला है। इसे दक्षिण कोरिया में परीक्षण के दौरान देखा गया है। फरवरी 2022 में भारत में लॉन्च होने के बाद से कैरेंस ने अच्छा कस्टमर बेस तैयार किया है और इसका फेसलिफ्ट मॉडल अगले साल पेश किया जा सकता है। आइए, इसके बारे में जान लेते हैं।

अपडेटेड Carens में क्या दिखा ?

स्पाई शॉट्स किआ कैरेंस फेसलिफ्ट के आगे और पीछे के हिस्सों में महत्वपूर्ण बदलावों की एक झलक प्रदान करते हैं। सबसे उल्लेखनीय अपडेट में से एक नई टेल-लाइट है, जिसमें अपडेटेड सेल्टोस और हाल ही में सोनेट फेसलिफ्ट पर देखी गई सी-आकार की एलईडी मोटिफ शामिल है।

हालांकि हेडलाइट का डिजाइन स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसके अपडेटेड सेल्टोस के साथ अलाइन होने की उम्मीद है। कैरेंस फेसलिफ्ट में संभवतः नए फ्रंट और रियर बंपर के साथ फिर से डिजाइन किए गए अलॉय व्हील दिए जाएंगे।

संभावित इंटीरियर अपडेट

उम्मीद है कि फेसलिफ्टेड कैरेंस में मौजूदा मॉडल का लेआउट बरकरार रहेगा, जो 6 और 7-सीट कॉन्फिगरेशन की पेशकश करेगा। हालांकि, फीचर लिस्ट में अपडेट के साथ डैशबोर्ड और अपल्होस्ट्री के लिए नए कपड़े और मैटेरिलय के इस्तेमाल की उम्मीद है।

इंजन और परफॉर्मेंस

कैरेंस फेसलिफ्ट को वर्तमान में 1.5-लीटर एनए पेट्रोल इंजन, 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन और 1.5-लीटर डीजल इंजन ऑफर किया गया है। इसका टर्बो-पेट्रोल यूनिट 6-स्पीड iMT और 7-स्पीड डुअल-क्लच गियरबॉक्स विकल्प प्रदान करता है। डीजल संस्करण तीन ट्रांसमिशन विकल्प प्रदान करता है। इसमें मैनुअल, आईएमटी, और 6-स्पीड टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक शामिल है।

क्या कहते हैं जीएसटी के आंकड़े?

डा. अश्विनी महाजन
कालेज एसोशिएट प्रोफेसर

इससे पहले वर्ष 2022-23 में आयातों से जीएसटी (उपकर समेत) औसतन 40196 करोड़ रुपए मासिक रहा। हालांकि जीएसटी पद्धति अपनाने के बाद देश में जीएसटी की प्राप्तियों में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिले। लेकिन जीएसटी की प्राप्तियां लगातार बढ़ती ही रही और उनमें खासी ग्रोथ भी देखने को मिल रहा है।

देखा गया है कि जीएसटी की प्राप्तियों में आयात पर लगाए गए कर और उपकर (सेस) भी शामिल हैं। उस दृष्टि से उपकर मिलाकर अप्रैल 2024 में आयात से कुल जीएसटी प्राप्तियां 38834 करोड़ रुपए की हैं। यदि यह कहा जाता है कि जीएसटी में होने वाली वृद्धि का एक कारण बढ़ते हुए आयात भी हैं, तो यह बात आंकड़ों से सिद्ध नहीं होती। गौरतलब है कि जहां अप्रैल 2024 को आयातों पर कर से जीएसटी प्राप्ति 38834 करोड़ रुपए रही है, तो पूरे वर्ष 2023-24 में आयातों से औसत जीएसटी (उपकर समेत) 41327 करोड़ रुपए मासिक रहा था। इससे पहले वर्ष 2022-23 में आयातों से जीएसटी (उपकर समेत) औसतन 40196 करोड़ रुपए मासिक रहा। हालांकि जीएसटी पद्धति अपनाने के बाद देश में जीएसटी की प्राप्तियों में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिले। लेकिन जीएसटी की प्राप्तियां लगातार बढ़ती ही रही और उनमें खासी ग्रोथ भी देखने को मिल रही है। जहां वर्ष 2023-24 में जीएसटी प्राप्ति की ग्रोथ 11.7 प्रतिशत रही, तो वहीं 2022-23 में यह 22 प्रतिशत थी, 2021-22 में यह 30 प्रतिशत थी...

कुछ समय से जीएसटी की बढ़ती प्राप्तियां देश की आर्थिकी में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। एक मई 2024 को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में जीएसटी प्राप्तियां पहली बार 2 लाख करोड रुपए को लांघती हुई 2.10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई हैं। पिछले साल के इस माह की तुलना में यह 12.4 प्रतिशत की वृद्धि है। लेकिन यदि रिफण्ड देने के बाद जीएसटी राशि की बात की जाए, तो यह अप्रैल 2024 में 1.92 लाख करोड़ रुपए है, जो अप्रैल 2023 की तुलना में 15.5 प्रतिशत की वृद्धि दिखाता है। यूं तो जीएसटी के प्रारंभ से ही, इसकी प्राप्तियों में निरंतर वृद्धि होती रही है, लेकिन वर्ष 2023-24 में जीएसटी की प्राप्तियां 20.18 लाख करोड़ रुपए की रही, जो वर्ष 2022-23 के 18.1 लाख करोड़ रुपए से 11.7 प्रतिशत अधिक थी। गौरतलब है कि 2022-23 की प्राप्तियां 2021-22 से 22 प्रतिशत अधिक थी। गौरतलब है कि जुलाई 2017 में देश के अधिकांश अप्रत्यक्ष करों (वस्तुओं व सेवाओं पर कर) को समाप्त करते हुए, उसके स्थान पर जीएसटी लगाया गया था। यह जीएसटी केंद्र और राज्यों को बीच बराबर बांट दिया जाता है। उसके अलावा वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार केंद्र के द्वारा लगाए गए करों का एक निश्चित प्रतिशत (जो वर्तमान में 42 प्रतिशत है), राज्यों को स्थानांतरित करने का प्रावधान है। इसके अनुसार भी राज्यों को जीएसटी का एक बड़ा हिस्सा मिलता है।

जीएसटी के विभिन्न घटक

जीएसटी के विभिन्न हिस्सों को यदि समझने का प्रयास करें तो अप्रैल 2024 में 2.1 लाख करोड़ रुपए की कुल जीएसटी प्राप्तियों में सेंट्रल जीएसटी 43846 करोड़ रुपए, स्टेट जीएसटी 53538 करोड़ रुपए, इंटीग्रेटिड जीएसटी 99623 करोड़ रुपए, जिसमें 37826 करोड़ रुपए आयातित वस्तुओं पर जीएसटी से प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा 13260 करोड़ रुपए उपकर (सेस) के रूप में प्राप्त हुए, जिसमें 1008 करोड़ रुपए आयातित वस्तुओं पर उपकर से प्राप्त हुए।

क्यों और कैसे बढ़ता है जीएसटी

जीएसटी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर लगता है। इसकी खासियत यह है कि यह उत्पादन प्रक्रिया में हर बार के मूल्य संवद्र्धन यानी वैल्यू एडीशन पर लगता है।

उत्पादन में वृद्धि

स्वाभाविक है कि देश में जैसे-जैसे वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ता है, जीएसटी की दर समान रहने पर भी जीएसटी की प्राप्तियां बढ़ जाती हैं। कोविड के बाद पिछले कुछ वर्षों में जीडीपी ग्रोथ न केवल पहले से बेहतर हुई है, बल्कि बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत लगातार सबसे तेजी से बढने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है। वर्ष 2021-22 में जीडीपी ग्रोथ 9.1 प्रतिशत, 2022-23 में 7 प्रतिशत रिकॉर्ड की गई। वर्ष 2023-24 के लिए अग्रिम अनुमानों के अनुसार 7.6 प्रतिशत जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है। इस ग्रोथ में सभी क्षेत्रों का योगदान रहा। पिछले कुछ वर्षों में औद्योगिक ग्रोथ की दर बढ़ी है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक अप्रैल 2021 में 126.1 की तुलना में जनवरी 24 तक 153.0 तक पहुंच गया है। सेवा क्षेत्र में भी उल्लेखनीय ग्रोथ देखने को मिल रही है। औद्योगिक और सेवा क्षेत्र की ग्रोथ के चलते जीएसटी की प्राप्तियां बढना अस्वाभाविक नहीं है।

कीमतों में वृद्धि

चूंकि जीएसटी वस्तुओं के मूल्य पर लगता है, यह मात्र वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन बढने से ही नहीं, बल्कि मुद्रास्फीति, यानी कीमतों में वृद्धि के कारण भी बढ़ता है। पिछले तीन वर्षों में देश में मुद्रास्फीति की दर में भी वृद्धि हुई है। यह वृद्धि घरेलू कारणों से कम, विदेशी कारणों से ज्यादा हुई है। अमरीका, यूरोप समेत दुनिया के अधिकांश मुल्क मुद्रास्फीति से जूझ रहे हैं। लेकिन कारण जो भी हो, मुद्रास्फीति भी कुछ मात्रा में जीएसटी में वृद्धि का कारण बन रही है।

अर्थव्यवस्था का औपचारीकरण

भारत में उत्पादन का बहुत बड़ा क्षेत्र अनौपचारिक यानी नॉन-फार्मल रहा है और कुछ हद तक आज भी है। लेकिन पिछले कुछ समय से कुछ स्वाभाविक कारणों से और कुछ हद तक जीएसटी लागू होने से अर्थव्यवस्था का औपचारीकरण बढ़ा है। समझना होगा कि पूर्व की उत्पादन प्रक्रिया पर लगे जीएसटी का क्रेडिट आगामी उत्पादन में तभी मिल सकता है, जब उत्पादन प्रक्रिया में संलग्न सभी घटक जीएसटी में पंजीकृत हों। इस कारण से भी अर्थव्यवस्था का औपचारीकरण बढ़ा है, जिसके चलते जीएसटी की प्राप्तियां भी बढ़ रही हैं।

क्या देश में आयात भी है जीएसटी बढने का कारण

देखा गया है कि जीएसटी की प्राप्तियों में आयात पर लगाए गए कर और उपकर (सेस) भी शामिल हैं। उस दृष्टि से उपकर मिलाकर अप्रैल 2024 में आयात से कुल जीएसटी प्राप्तियां 38834 करोड़ रुपए की हैं। यदि यह कहा जाता है कि जीएसटी में होने वाली वृद्धि का एक कारण बढ़ते हुए आयात भी हैं, तो यह बात आंकड़ों से सिद्ध नहीं होती। गौरतलब है कि जहां अप्रैल 2024 को आयातों पर कर से जीएसटी प्राप्ति 38834 करोड़ रुपए रही है, तो पूरे वर्ष 2023-24 में आयातों से औसत जीएसटी (उपकर समेत) 41327 करोड़ रुपए मासिक रहा था। इससे पहले वर्ष 2022-23 में आयातों से जीएसटी (उपकर समेत) औसतन 40196 करोड़ रुपए मासिक रहा। हालांकि जीएसटी पद्धति अपनाने के बाद देश में जीएसटी की प्राप्तियों में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिले। लेकिन जीएसटी की प्राप्तियां लगातार बढ़ती ही रही और उनमें खासी ग्रोथ भी देखने को मिल रही है। जहां वर्ष 2023-24 में जीएसटी प्राप्ति की ग्रोथ 11.7 प्रतिशत रही, तो वहीं 2022-23 में यह 22 प्रतिशत थी, 2021-22 में यह 30 प्रतिशत थी। माना जा सकता है कि सामान्यतः जीएसटी प्राप्तियों की ग्रोथ चालू कीमतों पर जीडीपी ग्रोथ से अधिक ही रही। यह इंगित करता है कि अब जीएसटी का दायरा बढने के साथ-साथ इससे प्राप्तियां स्वयंमेव बढ़ती जा रही हैं। यह भारत के आर्थिक परिदृश्य के लिए

संपादक की कलम से

पीएम की मुस्लिम अपील

बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ टीवी चैनलों को साक्षात्कार दिए थे। उनमें उन्होंने मुसलमानों को 'आत्मचिंतन' करने की अपील की थी और नसीहत भी दी थी। यह पहला मौका है कि देश के प्रधानमंत्री को मुसलमानों की इस तरह मनुहार करनी पड़ी है। प्रधानमंत्री ने किसी पार्टी का वोट बैंक या बंधक बनने के बजाय खुले दिमाग से सोचने की नसीहत भी दी है। प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि एक सीधी लकीर की तरह वोट देना और वह भी हिंदू वर्चस्व या हिंदू-विरोध के नाम पर भाजपा जैसे राष्ट्रवादी दलों के खिलाफ मुसलमानों का वोट करना एक गलत और पूर्वाग्रही ट्रेंड है। मौजू सवाल है कि चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री को मुसलमानों को, एक हद तक, मनाने या अपील करने को बाध्य क्यों होना पड़ा? हिंदू-मुस्लिम का चुनावी विभाजन तो 'जनसंघ' के दौर से रहा है। पहले जनसंघ और बाद में भाजपा बुनियादी और वैचारिक तौर पर हिंदूवादी पार्टी रही है। यह दीगर है कि अच्छी तादाद में मुसलमान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में भी भाजपा को वोट देते थे और आज प्रधानमंत्री मोदी के सूत्रवाक्य- 'सबका साथ, सबका विकास'' का समर्थन करते हुए 12-15 फीसदी मुसलमान भाजपा के पक्ष में वोट कर रहे हैं, लेकिन वह कभी भी 'निर्णायक' साबित नहीं हुआ। यकीनन देश की आजादी के बाद कांग्रेस अधिकांश समय सत्तारूढ़ रही। 1951 से 1975 तक तो कांग्रेस को कोई चुनौती ही नहीं थी, लिहाजा उसने अपनी चुनावी रणनीति के तहत मुसलमानों को 'वोट बैंक' की तरह बांधे रखा और दलितों, आदिवासियों, कुछ पिछड़ी जातियों में भी कांग्रेस के जनाधार बनाए। हालांकि केंद्र में वाजपेयी सरकार के 6 साल और मोदी सरकार के 10 साल के अलावा या तो कांग्रेस सत्ता में रही है अथवा बाहरी समर्थन से लडख़ड़ाती सरकारें बनवाई हैं। दरअसल जब कांग्रेस से अलग होकर या उसका विरोध करते हुए क्षेत्रीय दलों के उभार का दौर आया, तो मुसलमान सपा, बसपा, राजद और तृणमूल कांग्रेस आदि क्षेत्रीय दलों की ओर भी ध्रुवीकृत हुए। नतीजतन मुस्लिम वोट बंटते रहे हैं, लेकिन मुस्लिम आज भी मानसिक तौर पर कांग्रेस के साथ हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 'आत्मचिंतन' की नसीहत इसलिए दी है, ताकि मुसलमान सोच सकें कि जिन्होंने उन्हें वोट बैंक का बंधक बनाए रखा, उन्होंने आखिर क्या दिया है? मुसलमानों को क्या फायदे मिले हैं? इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी ने 1992 के कथित बाबरी मस्जिद विध्वंस, 2002 के गोधरा सांप्रदायिक दंगों का जिक्र किया है। किसी प्रधानमंत्री ने शायद यह भी पहली बार कहा है कि यदि एक सांप्रदायिक वृत्तांत गढने की कोशिश न की गई होती और मुसलमानों के रहनुमा बनकर अपने खेमे में बांधे रखने की सियासत नहीं की गई होती, तो ये दोनों दौर उतने भयावह न होते! उप्र के मुख्यमंत्री के तौर पर मुलायम सिंह को 'रामसेवकों' पर गोलियों की बौछार नहीं करनी पड़ती! प्रधानमंत्री ने तीन तलाक से लेकर शाहबानो तक के संदर्भ भी उठाए हैं। 'सच्चर कमेटी' के निष्कर्षों का भी जिक्र किया, लेकिन रंगनाथ मिश्रा आयोग का हवाला देने भूल गए अथवा उसे जरूरी नहीं समझा। उसी आयोग ने अनुशंसा की थी कि धार्मिक आधार पर भी आरक्षण दिया जा सकता है। मुसलमानों को अल्पसंख्यक के तौर पर 15 फीसदी में से 10 फीसदी आरक्षण दिया जाए। आयोग ने ओबीसी आरक्षण में से मुसलमानों को आरक्षण मुहैया कराने का भी रास्ता सुझाया था। बहरहाल संसद ने इस आयोग की सिफारिशें पारित नहीं होने दीं। दरअसल आज यह सवाल नहीं, बल्कि हकीकत है कि औसत मुसलमान को गरीबी, अशिक्षा, बदहाली और भुखमरी ही मिली। अब आम चुनाव में मुस्लिम आरक्षण के जरिए वोट बैंक को भुनाने की सियासी कवायद जारी है, जिसके पलटजवाब में प्रधानमंत्री मोदी को अपने दलित, आदिवासी और ओबीसी समर्थक जमातों को विश्वास दिलाना पड़ रहा है कि मोदी मुस्लिम आरक्षण लागू नहीं होने देगा। सारांश यह है कि मौजूदा दौर 'मुस्लिममय' हो गया है और हिंदू-मुस्लिम में विभाजित चुनाव हो गया है, लिहाजा प्रधानमंत्री को 'आत्ममंथन' करने की मनुहार तक करनी पड़ी है।

राय

असत्य व राजनीति

इतिहास भी कमाल के गोते लगाता है! भला सोचिए, 2024 में वह 1927 की कहानी दोहरा रहा है। तब यानी 1927 में एक थीं कैथरीन मेयो और एक थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कौन थे यह तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन कैथरीन मेयो कौन थीं यह जानने की जरूरत अधिकांश पाठकों को पड़ेगी। वे एक अमरीकी, श्वेत चमड़ी की श्रेष्ठता के भाव से भरी, नकचढ़ी पत्रकार सरीखी कुछ थीं जिन्हें कुछ लोग तब उसी तरह इतिहासकार भी कहते थे। 1920 के दशक में मिस मेयो भारत आई थीं, गांधीजी से भी मिली थीं, दूसरी हस्तियों से भी मिली थीं, रवींद्रनाथ ठाकुर से भी मिली थीं। गांधीजी के निर्देश में चल रहे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से असहमत, असंतुष्ट, नाराज मेयो मैडम ने एक किताब लिखी : 'मदर इंडिया!' ना, ना, आप ऐसा मत मान बैठिएगा कि महबूब खान की प्रसिद्ध फिल्म 'मदर इंडिया' मेयो मैम की इस किताब से प्रेरित थी। मेयो मैम 'मदर इंडिया' में अपना अलग ही राग अलापती हैं। यह किताब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों, उसकी दिशा, उसकी उपलब्धियों आदि की धज्जियां उड़ाती हुई यह साबित करती है कि भारतीय समाज कुरीतियों, अन्याय, अत्याचार तथा शोषण की गंदी व्यवस्था पर टिका एक ऐसा गर्हित समाज है जिसे गुलाम बनाकर गोरी चमड़ी वाले अंग्रेजों ने कुछ सभ्य, कुछ मानवीय बनाया है। मेयो मैम की किताब तब कई लोगों को नागवार गुजरी थी और वह जल्दी ही 'गुजर भी जाती' यदि गांधीजी ने उसे पढ़ा न होता। बहुत कहने पर गांधीजी ने न केवल 'मदर इंडिया' पढ़ी, बल्कि चौतरफा आग्रह के कारण 'बहुत व्यस्तता' में से समय निकालकर उस पर एक टिप्पणी भी लिखी जो 15 सितंबर 1927 को 'यंग इंडिया' में प्रकाशित हुई। महात्मा गांधी ने अपनी टिप्पणी का शीर्षक दिया : 'ड्रेन इंस्पेक्टर रिपोर्ट' : नाली सफाई जमादार की रिपोर्ट! गरज यह कि जिसका धंधा ही गंदगी को उकेर-उकेर कर देखना है, वह गंदगी के अलावा देखेगा भी तो क्या? और वर्णन भी करेगा तो गंदगी का ही करेगा। महात्मा गांधी की शैली में यह खासी कड़ी टिप्पणी थी। गांधीजी ने लिखा कि 'यह बड़ी चालाकी से लिखी गई सशक्त किताब है, जो किसी हद तक सत्य का बखान, असत्य के प्रचार के लिए करती है।' अब न कैथरीन मेयो हैं, न गांधीजी, लेकिन गंदगी फैलाने का धंधा जोरों पर है। गंदगी को सहेजने तथा 'बड़ी चालाकी से सत्य का बखान इस तरह करना कि असत्य का प्रचार हो' वाली संस्कृति जीवित भी है, जारी भी। प्रधानमंत्री ने इस कला में महारत हासिल कर ली है। वे अब इस कला के 'उस्ताद' बन गए हैं। हम देखें तो प्रधानमंत्री का कुल इतिहास 2014 से शुरू होता है और कुर्सी तक पहुंचकर चुक जाता है। वे सत्ता की जिन दो कुर्सियों पर बैठे हैं- मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री- यदि वे कुर्सियां हटा दी जाएं तो उनके पास कुछ भी बचता नहीं है। चुनाव के सन्निपात में इधर जब-जब मुंह खोल रहे हैं, इतिहास का मुंह खुला का खुला रह जाता है।

वैसे भी प्रधानमंत्री झूठ व सच में फर्क करने जैसी नैतिकता में पड़ते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का चुनाव घोषणापत्र उन्हें मुस्लिम लीग के घोषणापत्र जैसा लगता है। कोई प्रमाण? कोई साम्यता? नहीं, यह सब बताना प्रधानमंत्री का काम थोड़े ही है! उन्हें पता है कि उनकी बात को गोदी मीडिया देश भर में पहुंचा देगा। आज राजनीति में अधिकतर नेता असत्य बोलते हैं।

निराशाजनक है कम मतदान होना

मतदान के कत्र्तव्य को हर हाल में अनिवार्य बनाया जाना समय की मांग है। मतदान करने के उपरांत ही कोई नागरिक अपने अधिकारों के लिए दावा करने का पात्र हो, यह बहुत आवश्यक है, अन्यथा लोकतंत्र मजाक बन कर रह जाएगा। लोकतंत्र की मजबूती के लिए वोट से चोट करना आवश्यक है। हम सभी अपने वोट के अधिकार का मूल्य समझें

भारत लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक व्यवस्था का देश है। यह देश विश्व की महान लोकतंत्रात्मक प्रणालियों में से एक है। लोकतंत्र का आशय ही लोगों की बनाई गई एक व्यवस्था या प्रणाली है जिसके सिद्धान्तों के आधार पर यह स्वतः ही कार्य करती है। इस प्रणाली का संचालन लोगों द्वारा ही होता है। लोकतंत्र में लोगों की आशाओं, आकांक्षाओं, अपेक्षाओं तथा आवश्यकताओं के अनुरूप ही कार्य होता है। इस व्यवस्था में लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह व्यवस्था लोगों की, लोगों के लिए तथा लोगों के द्वारा ही संचालित होती है। लोकतंत्र या प्रजातन्त्र निर्वाचन या चुनाव से मजबूत होता है। चुनाव निष्पक्ष, निर्भीक, बिना डर, भय एवं स्वेच्छा से होता है। चुने हुए प्रतिनिधि लोगों के सेवक बनकर बिना पक्षपात तथा भेदभाव से जनभावनाओं के अनुरूप कार्य करते हैं। लोकतंत्र या प्रजातन्त्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसके अन्तर्गत जनता अपनी स्वेच्छा से निर्वाचन प्रक्रिया में आए हुए किसी भी मनपसंद उम्मीदवार को मत देकर अपना प्रतिनिधि चुनती है। यानी लोकतन्त्र शासन का एक ऐसा रूप जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है। एक ऐसी व्यवस्था जिसके अनुसार जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि शासक या सेवक बनकर राज्य में जनता की सेवा करता है। लोकतंत्र शासकीय प्रणाली का एक बहुत सुन्दर रूप है। भारत में 26 जनवरी, 1950 को संविधान लागू हुआ।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार कोई भी भारतीय व्यक्ति यदि वह 18 वर्ष की आयु पूर्ण करता हो, वह इस प्रणाली के लिए बिना डर या भय तथा अपनी स्वेच्छा से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। यह उसका संवैधानिक अधिकार है। लोकतंत्र की नींव ही वोट के अधिकार पर टिकी है। इसलिए संवैधानिक दृष्टि से यह किसी भी भारतीय नागरिक का वह अधिकार है जो लोकतन्त्र को सशक्त बनाने का कार्य करता है। विडम्बना है कि भारतीय संविधान लागू होने के 75 वर्षों के बाद भी हम इसका महत्व तथा उपयोगिता नहीं समझ पाए हैं। आज भी लोग मतदान करने में अनिच्छा तथा उदासीनता दिखाते हैं। प्रत्येक चुनाव में कर्मचारियों, अधिकारियों, गैर सरकारी तथा अद्र्धसरकारी संस्थानों में काम करने वाले दिहाड़ीदार मजदूरों को वोट डालने के लिए वेतन सहित छुट्टी का प्रावधान रहता है, लेकिन उसके बावजूद लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने में रुचि नहीं दिखाते। इसके बहुत से कारण हैं जिनमें अशिक्षित होना, लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास नहीं रखना या संवैधानिक कर्तव्यों की अनदेखी करना है। यह देश अपने नागरिकों को सब कुछ प्रदान करता है। शिक्षा, सेवा, सडक़, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, बिजली, पानी, जीविकोपार्जन के सभी संसाधन तथा सिर उठाकर जीने की स्वतन्त्रता यह राष्ट्र प्रदान करता है। यह देश संविधान के अनुसार संचालित है।

यही लोकतंत्रिक प्रणाली को मजबूती प्रदान करता है। अफसोस है कि हम वोट डालने के संवैधानिक अधिकार का पालन ही नहीं करते। आज भी सरकारों को अधिक मतदान करने के लिए लोगों को शिक्षित एवं जागरूक करने के उद्देश्य से अभियान चलाने पड़ते हैं। आज भी वोट डलवाने के लिए लोगों से निवेदन तथा आग्रह करना पड़ता है। हमें यह समझना चाहिए कि लोकतन्त्र में जहां वोट डालना हमारा अधिकार है, वहीं यह हमारा संवैधानिक कर्तव्य भी है।

अ_ारहवीं लोकसभा के गठन के लिए चुनाव प्रतिशत को बढ़ाने की भारतीय चुनाव आयोग की कोशिशों के बावजूद अभी तक सम्पन्न हुए तीन लोकसभा चुनाव चरणों में यह आंकड़ा निराशाजनक ही रहा है। चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए इन आंकड़ों के प्रथम चरण में 66.14 प्रतिशत, द्वितीय चरण में 66.71 प्रतिशत तथा तृतीय चरण में 65.68 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जो कि वर्ष 2019 की तुलना में बहुत कम है। वर्तमान में चुनाव आयोग द्वारा वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए बहुत से अभियान चलाए जा रहे हैं। पाठशालाओं, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में रैलियों, भाषणों तथा अनेक प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। पूरे देश में 'स्वीप' यानी 'सिस्टेमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलैक्टोरल पार्टिसिपेशन' कार्यक्रम के माध्यम से जन जागरण हो रहा है।

इसके बावजूद कम संख्या में मतदान होना निराशाजनक है। अधिकार एवं कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। हम स्वतंत्र भारत में अपने अधिकारों का दावा तो करते हैं, परन्तु अपने कर्तव्यों के लिए जागरूक नहीं हैं। जो राष्ट्र हमें सम्मान के साथ जीने के लिए सभी संसाधन प्रदान करता है, उसकी नींव को मजबूती के लिए हम मतदान करने का कर्तव्य नहीं निभा सकते? यह बहुत ही चिंताजनक, शर्मनाक तथा दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि कोई नागरिक व्यवस्था से नाखुश है या उम्मीदवारों को पसंद नहीं करता तो भी 'नोटा' का प्रावधान है, लेकिन वोट न डालना किसी समस्या का समाधान नहीं है। बिजली, पानी, सडक़, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार के लिए हम लम्बे समय तक कार्यालयों के चक्कर लगा सकते हैं, लेकिन मतदान के संवैधानिक कर्तव्य का उपयोग करने के लिए हम मतदान केंद्र पर नहीं जा सकते? जहां आधार कार्ड, हैल्थ कार्ड, किसान कार्ड, रोजगार कार्ड तथा राशन कार्ड से प्रत्येक नागरिक का अधिकार निश्चित होता है, वहीं पर आज आवश्यक है कि मतदान कार्ड का उपयोग भी सुनिश्चित हो। मतदान के कर्तव्य को हर हाल में अनिवार्य बनाया जाना समय की मांग है।

मतदान करने के उपरान्त ही कोई नागरिक अपने अधिकारों के लिए दावा करने का पात्र हो, यह बहुत आवश्यक है, अन्यथा लोकतन्त्र मजाक बन कर रह जाएगा। लोकतंत्र की मजबूती के लिए वोट से चोट करना आवश्यक है। हम सभी अपने वोट के अधिकार का मूल्य समझकर चुनावी यज्ञ में अपनी आहुति दें, इसी में ही लोकतन्त्र की विजय है। एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक बन कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर गौरवान्वित महसूस करें। तभी अगले चरणों में मतदान प्रतिशत बढ़ पाएगा।

पीए सिद्धार्थ

भविष्य पुराण'

दिलीप कुमार अभिनीत फिल्म 'गोपी' में राजेन्द्र कृष्ण के गीत 'रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलियुग आएगा' पर भविष्य पुराण का कितना असर है, इस बारे कहना कठिन है। गीत में हंस के दाना दुनका चुगने और कौए के मोती खाने का जिक्र तो है, पर गधों और घोड़ों का कहीं उल्लेख नहीं आता। जबकि केन्द्र सरकार के एक प्रभावशाली मंत्री पिछले दिनों अपने सम्बोधन में कह रहे थे कि अजब दौर है कि घोड़ों को घास नहीं मिलता, पर गधे च्यवनप्राश खा रहे हैं। इससे इतना तो तय है कि वह ख़ुद को घोड़ा बता रहे थे। लेकिन वह जिन गधों की तरफ इशारा कर रहे थे, वे सत्ता का भरपूर आनन्द लूट रहे हैं। भविष्य पुराण में न गधों और घोड़ों का जिक्र है और न ही 21वीं सदी का। सत्ता का चरित्र हर युग में एक जैसा ही रहता आया है और आम आदमी की किस्मत भी। भविष्य पुराण के चार पर्वों में शामिल प्रतिसर्ग पर्व में घटनाएं घटित होने के बाद कालान्तर में जोड़ी गई हैं। ऐसे में इसे भविष्य पुराण कहा जाए या अतीत पुराण, इसका फैसला आप ही करें। लेकिन मैं कलियुग के उन लक्षणों का हवाला अवश्य देना चाहूंगा जिसके बारे में श्रीराम ने सीता को बताया था। पंचवटी में सावन की घटाओं का आनन्द उठाते हुए अपनी कुटिया में बैठे प्रभु श्रीराम से जब सिया ने कलियुग के लक्षणों के बारे में पूछा तो प्रभु ने कहा कि घोर कलियुग के दौर में न धर्म बचेगा और न ही कर्म। ऐसे में शर्म होने या आने के सवाल स्वतः समाप्त हो जाएंगे। राजा और प्रजा, दोनों नैतिक रूप से नग्न होकर घूमेंगे। कहने को लोकतंत्र होगा। लोगों को अपना राजा चुनने का अधिकार होगा। पर चुना हुआ राजा तमाम तरह के कुकर्मों पर आंखें मीचे अपने कुकर्मी सामन्तों को अभयदान प्रदान करता रहेगा।

कोतवाल बलात्कारियों को सलाम ठोकेंगे। अगर कहीं पकड़े जाने की नौबत आई तो वे राज्य की मदद से विदेश भाग जाएंगे। राजस्व पर हाथ साफ करने वालों को राजा की शरण में जाने पर न केवल अभयदान मिलेगा बल्कि सामन्ती भी प्राप्त होगी। अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए राजा मेरे नाम पर वोट मांगेगा। सामन्त राजा के साथ मेरे नाम का कीर्तन करेंगे। राजा अपने फायदे के लिए प्रजा की गैसलाइटिंग करेगा अर्थात मनोवैज्ञानिक तौर पर उसे धोखे में रखते हुए इस तरह भ्रमित करेगा कि प्रजा अपने विचारों और ख़ुद की क़ाबिलियत पर शक करने लगेगी। प्रजा के पेट में रहने वाले कीड़े उसके दिमाग़ में अपना घर बना लेंगे। राजा आत्ममुग्धता का इतना अधिक आदी होगा कि जगह-जगह उसके फोटो वाले होर्डिंग और बोर्ड लगे होंगे। यहां तक कि राज्य द्वारा बनाए जाने वाले सार्वजनिक शौचालयों के बाहर, दरवाज़ों और टॉयलेट पेपर पर भी उसके फोटो चिपके होंगे। अपनी छवि निर्माण के लिए वह झूठ का इस क़दर सहारा लेगा कि झूठ भी 'त्राहिमाम त्राहिमाम' कर उठेगा। अपनी छवि चमकाने के लिए राजा सरकारी मशीनरी से इतना प्रचार करेगा कि कालान्तर में यह अभियान प्रोपेगेंडा या अधिप्रचार में बदल जाएगा। लेकिन इसमें प्रजा भी बराबर की हिस्सेदार होगी। सतयुग से अपने उत्थान के लिए किसी अवतार की परिकल्पना में खोई रहने वाली प्रजा कलियुग में सरकारी सुविधाओं का उपभोग करते हुए अपने कत्र्तव्यों से विमुख रहेगी।

अगर मुफ्त में ज़हर भी बंटेगा तब भी लोग यह सोचकर, उसे लेने के लिए क़तारबद्ध हो जाएंगे कि लेकर रख लेते हैं, कभी न कभी तो यह काम आएगा ही। संविधान के अनुसार स्वतंत्र प्रजा जब मनोवैज्ञानिक रूप से पीड़ित किसी व्यक्ति को राजा चुनेगी, तब उसके भयंकर परिणाम सामने आएंगे। दूसरों की बहु-बेटियों से व्यभिचार करने वाले और भ्रष्टाचारियों को सदन भेजने वाली जनता कभी यह नहीं सोचेगी कि कल उनके साथ भी ऐसा हो सकता है।

परिणामस्वरूप पूरे देश में अराजकता छाई रहेगी। किसी महामारी से छुटकारा पाने के लिए राज्य की ओर से लोगों को लगाए जाने वाले टीकों में पानी भरा होगा। इसके बावजूद अंधभक्त दावा करेंगे कि इन टीकों की वजह से ही वे पूरी तरह तंदरुस्त हैं।

F&O में बेलगाम तेजी पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जताई चिंता, जोखिमों को लेकर किया आगाह

परिवहन विशेष न्यूज

बाजार नियामक सेबी के एक अध्ययन से पता चला है कि 10 में से नौ खुदरा निवेशकों को वायदा और विकल्प कारोबार में नुकसान होता है। वित्त मंत्री ने बीएसई से कड़े अनुपालन और मजबूत रेगुलेटरी मानकों के जरिये निवेशकों का भरोसा बढ़ाने के लिए सेबी के साथ मिलकर काम करने की भी अपील की। वित्त मंत्री ने कहा उन्होंने कहा कि पारिवारिक बचत में एक पीढ़ीगत बदलाव हुआ है।

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को खुदरा निवेशकों को वायदा एवं विकल्प (F&O) कारोबार के जोखिमों को लेकर आगाह करते हुए कहा कि इसमें बेलगाम तेजी भविष्य में परिवारों की जमा-पूंजी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है।

देश के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि इस खंड में खुदरा कारोबार में कोई भी बेलगाम तेजी न केवल बाजार के लिए बल्कि निवेशकों की भावनाओं के लिए भी समस्याएं पैदा कर सकती है। उन्होंने कहा कि पारिवारिक बचत में एक पीढ़ीगत बदलाव हुआ है। हम उसे सुरक्षित रखना चाहते हैं।

बाजार नियामक सेबी के एक अध्ययन से पता चला है कि 10 में से नौ खुदरा निवेशकों को वायदा और विकल्प कारोबार में नुकसान होता है। वित्त मंत्री ने बीएसई से कड़े अनुपालन और मजबूत रेगुलेटरी मानकों के जरिये निवेशकों का भरोसा बढ़ाने के लिए सेबी के साथ मिलकर काम करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि बीएसई और एनएसई को प्रणालीगत जोखिम को कम करना चाहिए तथा बाजार की स्थिरता सुनिश्चित करनी चाहिए।

समाचार एजेंसी रायटर ने अप्रैल में दो सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा था कि सेबी डेरिवेटिव बाजारों में उछाल से उत्पन्न होने वाले जोखिमों का आकलन करने और यदि आवश्यक हो तो नीति में बदलाव का सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन करेगा।

ITR भरने से पहले चेक कर लें अपना एआईएस, गलती ठीक कराने का मिलेगा मौका

परिवहन विशेष न्यूज

टैक्स विशेषज्ञों ने बताया कि नौकरी करने वाला एक आदमी म्युचुअल फंड शेयर बाजार एलआईसी जैसी कई जगहों पर निवेश करता है और खरीद-फरोख्त करता है। म्युचुअल फंड कंपनी शेयर बाजार जैसे माध्यम इनकम टैक्स विभाग को हमारी खरीद-फरोख्त की जानकारी देते हैं। लेकिन इसमें गलती भी हो सकती है। जानकारी में बदलाव की जरूरत है तो एआईएस में संशोधन कर दिया जाएगा।

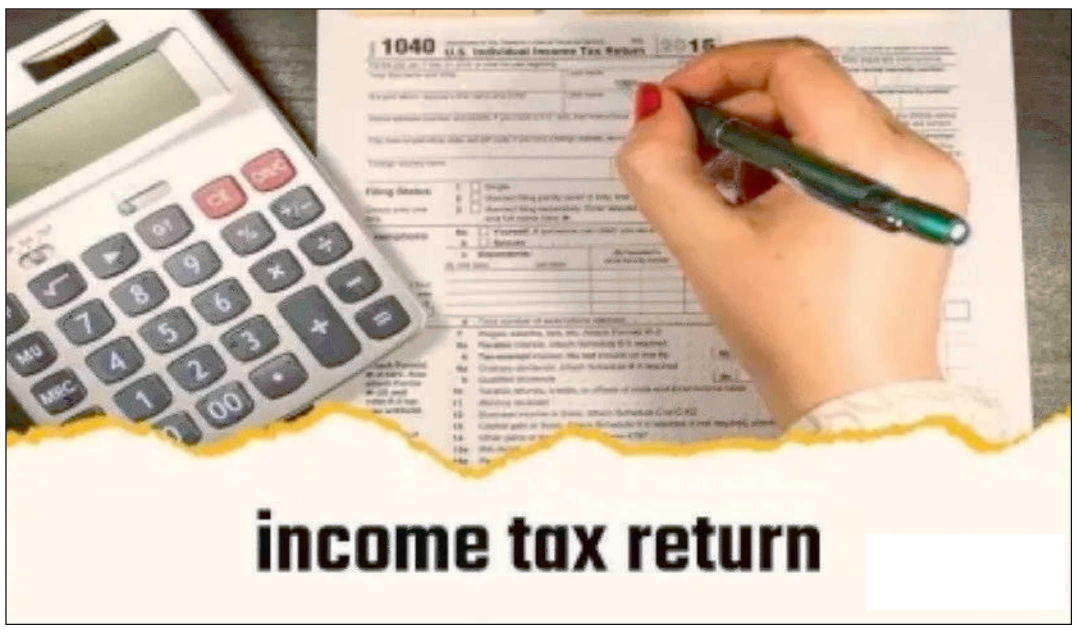

नई दिल्ली। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने से पहले अपना वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) जरूर चेक कर लें। उस विवरण में कोई गलती है तो इनकम टैक्स विभाग को अपना फीडबैक भी दे ताकि उस गलती को विभाग सुधार सके। अभी एआईएस में रियल टाइम फीडबैक देने की सुविधा नहीं है। पहली बार इनकम टैक्स विभाग की तरफ से यह सुविधा शुरू की गई है।

अब दे सकेंगे रियल टाइम फीडबैक

एआईएस में साल भर के दौरान किए गए वैसे सभी वित्तीय लेन-देन का पूरा विवरण होता है जिस पर टैक्स लिया जा सकता है। आईटीआर से जुड़े ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर अपने एआईएस को देखा जा सकता है। अब एआईएस में दिखाए गए विवरण पर रियल टाइम फीडबैक भी दे सकेंगे। वह फीडबैक उसी समय उस सोर्स के पास चला जाएगा जहां से इनकम टैक्स विभाग ने वह जानकारी ली है। फिर उस सोर्स ने क्या जवाब दिया है, इसकी जानकारी भी आयकरदाता को मिल जाएगी। जानकारी में बदलाव की जरूरत है तो एआईएस में संशोधन कर दिया जाएगा।

इनकम टैक्स विभाग एआईएस में कर देगा संशोधन

टैक्स विशेषज्ञों ने बताया कि नौकरी करने वाला एक आदमी म्युचुअल फंड, शेयर बाजार, एलआईसी जैसी कई जगहों पर निवेश करता है और खरीद-फरोख्त करता है। म्युचुअल फंड कंपनी, शेयर बाजार जैसे माध्यम इनकम टैक्स विभाग को हमारी खरीद-फरोख्त की जानकारी देते हैं। लेकिन इसमें गलती भी हो सकती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 60,000 रुपए मूल्य के शेयर बेचे, लेकिन एआईएस में यह दिखा रहा है कि उसने एक लाख रुपए के शेयर बेचा है। इस जानकारी पर वह अपना फीडबैक देगा जो शेयर कंपनी के पास चला जाएगा और अगर वह कंपनी यह फीडबैंक देती है कि हां, उस व्यक्ति ने एक लाख रुपए का नहीं, 60,000 रुपए मूल्य का शेयर बेचा है तो इनकम टैक्स विभाग एआईएस में संशोधन कर देगा। अगर वह इस फीडबैक को अस्वीकार कर देता है तो एआईएस में कोई बदलाव नहीं होगा।

बिल्कुल सही आईटीआर भर सकेंगे लोग

चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए) और टैक्स एक्सपर्ट एम.के. गुप्ता ने बताया कि इसका फायदा यह होगा कि लोग बिल्कुल सही आईटीआर भर सकेंगे। अभी अगर एआईएस में गलत सूचना भी होती है तो लोग उसे सही मानकर टैक्स भर देते हैं। इस सुविधा से पारदर्शिता बढ़ेगी और अनुपालन आसान हो जाएगा। एआईएस के विवरण पर फीडबैक देने के बाद सोर्स की तरफ दी गई प्रतिक्रिया की तारीख तक की जानकारी आयकरदाता को मिलेगी।

2024 में वैश्विक वृद्धि में जारी रहेगा एशिया का 60% योगदान

IMF के उप प्रबंध निदेशक ओकामुरा का कहना है कि इस वर्ष यानी 2024 के दौरान भी एशियाई देश वैश्विक विकास का इंजन बने रहेंगे और यह वैश्विक वृद्धि में 60 प्रतिशत योगदान के लिए सही राह पर हैं। इस कठिन माहौल में बढ़ती खर्च मांगों को पूरा करने और भविष्य के झटकों के खिलाफ लचीलापन बनाने के लिए सरकारी बजट को घरेलू राजस्व जुटाना आवश्यक है।

नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के उप प्रबंध निदेशक ओकामुरा का कहना है कि इस वर्ष यानी 2024 के दौरान भी एशियाई देश वैश्विक विकास का इंजन बने रहेंगे और यह वैश्विक वृद्धि में 60 प्रतिशत योगदान के लिए सही राह पर हैं।

वैश्विक अर्थव्यवस्था ने महामारी के बाद के लगातार झटकों के प्रति आश्चर्यजनक लचीलापन दिखाया है। आईएमएफ ने अपने ताजा विश्व आर्थिक परिदृश्य में उम्मीद जताई है कि इस वर्ष वैश्विक वृद्धि 3.1 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी।

वहीं 13वें आईएमएफ-जापान उच्च स्तरीय सम्मेलन में ओकामुरा ने कहा कि एशिया महंगाई पर काबू पाने में सबसे आगे है। एशिया के अधिकांश देशों को 2024 में केंद्रीय बैंक के लक्ष्य तक पहुंचने की उम्मीद है।

उन्होंने कहा कि इस कठिन माहौल में बढ़ती खर्च मांगों को पूरा करने और भविष्य के झटकों के खिलाफ लचीलापन बनाने के लिए सरकारी बजट को घरेलू राजस्व जुटाना आवश्यक है।

इनसाइड

पोस्ट ऑफिस स्कीम में निवेश के लिए बदला नियम! ये गलती की, तो नहीं जमा कर पाएंगे पैसा

पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाएं काफी अच्छा ब्याज देती हैं। साथ ही इनमें आपका पैसा भी सुरक्षित रहता है। यही वजह है कि पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाओं में बड़ी संख्या में लोग निवेश करते हैं। इनमें निवेश और रिटर्न के साथ निवेश की शर्तों भी अलग-अलग हो सकती हैं।

नई दिल्ली। पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाएं काफी अच्छा ब्याज देती हैं। साथ ही, इनमें आपका पैसा भी सुरक्षित रहता है। यही वजह है कि पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाओं में बड़ी संख्या में लोग निवेश करते हैं। इनमें निवेश और रिटर्न के साथ निवेश की शर्तों भी अलग-अलग हो सकती हैं। लेकिन, एक नियम हर किसी के लिए समान है, और वह है, पैन-आधार की जानकारी देना।

नियमों में क्या हुआ है बदलाव?

पिछले साल 1 अप्रैल से पोस्ट ऑफिस की किसी भी योजना में निवेश करने के लिए पैन और आधार की जानकारी देना अनिवार्य है। अगर इन दोनों में कोई भी अंतर होता है, जैसे कि नाम या फिर जन्म तिथि, तो आप पोस्ट ऑफिस स्कीम में इन्वेस्ट नहीं कर सकते।

पैन वैलिडेशन के लिए कोर बैंक सॉल्यूशन (CBS) सिस्टम को Protean ई-गॉव टेक्नोलॉजीज (पहले NSDL) के साथ जोड़ा गया है।

जारी हुई सोने और चांदी की नई कीमतें, जानिए आज क्या रहा भाव

परिवहन विशेष न्यूज

सोने की कीमत में मंगलवार को गिरावट देखने को मिली है। राजधानी दिल्ली में मंगलवार 200 रुपये की गिरावट के साथ इसका भाव 72950 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। बात करें चांदी की तो इसके दाम 800 रुपये बढ़े। इस बढ़त के साथ चांदी के दाम प्रति किलो 86000 रुपये पर पहुंच गए। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने की कीमत में गिरावट दर्ज की गई है।

नई दिल्ली। सोने की कीमत में लगातार दूसरे दिन भी गिरावट देखने को मिली है। मंगलवार को सोने का भाव 200 रुपये टूटकर 72,950 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के मुताबिक दुनियाभर के बाजारों में सोने की कीमत में यही रुझान देखने को मिले हैं। इससे पहले सोमवार को 10 ग्राम सोने की कीमत 73,150 रुपये थी।

चांदी के कीमत की बात करें तो इसमें तेजी देखने को मिली है। आज इसके दाम 800 रुपये बढ़कर प्रति किलो 86,000 रुपये पर पहुंच गए। इससे पहले सोमवार को सिल्वर की कीमत 85,200 रुपये पर थी।

200 रुपये कमजोर हुआ सोना

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के सीनियर एनालिस्ट सौमिल गांधी के मुताबिक, राजधानी दिल्ली में मंगलवार को सोना (24 कैरेट) प्रति दस ग्राम 72,950 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। पिछले कारोबारी सत्र के मुकाबले इसमें 200 रुपये की कमी आई है। विदेशी बाजार की बात करें तो Comex में सोना प्रति ओन्स 2,339 डॉलर पर कारोबार कर रहा है। इसमें पिछले सत्र के मुकाबले 8 डॉलर की कमी देखने को मिली है।

सोने को छोड़ दूसरी स्कीम में पैसा लगा रहे निवेशक

सौमिल गांधी ने बताया कि अमेरिका में महंगाई का दबाव लगातार बना हुआ है। इससे फेडरल रिजर्व ब्याज में कटौती के फैसले को टाल सकता है। इससे निवेशक सोने को छोड़कर उन स्कीमों में पैसे लगा रहे हैं, जहां उन्हें अच्छा ब्याज मिलेगा।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी चांदी की कीमत में उछाल देखने को मिला है। चांदी का भाव 28.35 डॉलर प्रति ओन्स पर पहुंच गया। पिछले सत्र में यह 28.10 डॉलर पर ट्रेड कर रहा था।

रॉकेट बने अडानी ग्रुप के स्टॉक, 5 फीसदी से ज्यादा उछले इन कंपनियों के शेयर

परिवहन विशेष न्यूज

अदाणी समूह (Adani Group) की ज्यादातर कंपनियों में मंगलवार को जबरदस्त तेजी दर्ज की गई। अदाणी एंटरप्राइजेज अदाणी टोटल गैस और अदाणी पावर में 5 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हुई। अदाणी ग्रीन एनर्जी में 4.34 प्रतिशत और एसीसी में 4.17 प्रतिशत का उछाल दिखा। आइए जानते हैं कि इस तेजी की वजह क्या है और अदाणी समूह की बाकी कंपनियों का क्या हाल रहा।

नई दिल्ली। अदाणी समूह (Adani Group) की ज्यादातर कंपनियों में मंगलवार को जबरदस्त तेजी दर्ज की गई। अदाणी एंटरप्राइजेज, अदाणी टोटल गैस और अदाणी पावर में 5 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हुई। अदाणी ग्रुप की दूसरी कंपनियों ने का प्रदर्शन भी शानदार रहा। ग्रुप की सभी कंपनियों के शेयर हरे निशान में बंद हुए।

कौन शेयर कितना बढ़ा?

अरबपति कारोबारी गौतम अदाणी की अगुआई वाले ग्रुप की प्रमुख कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज के शेयरों में बीएसई पर 5.43 प्रतिशत की तेजी आई। अदाणी टोटल गैस का स्टॉक 5.50 प्रतिशत, अदाणी पावर 5.49 प्रतिशत, अदाणी ग्रीन एनर्जी 4.34 प्रतिशत और एसीसी 4.17 प्रतिशत उछला।

ग्रुप की बाकी कंपनियों में अच्छी तेजी दिखी। अंबुजा सीमेंट्स के शेयर 3.90 फीसदी, अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस के शेयर 3.07 फीसदी, अदाणी विल्मर (2.20 फीसदी), अदाणी पोर्ट्स (1.89 फीसदी) और एनडीटीवी (1.87 फीसदी) चढ़े। सभी 10 सूचीबद्ध कंपनियों का कुल मार्केट वैल्यूएशन 15,86,018.55 करोड़ रुपये हो गया।

इक्विटी मार्केट में 30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स 328.48 अंक या 0.45 फीसदी चढ़कर 73,104.61 पर बंद हुआ। NSE निफ्टी 113.80 अंक यानी 0.51 फीसदी बढ़कर 22,217.85 पर पहुंच गया।

निवेश के प्लान का असर?

अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के एक टॉप एग्जीक्यूटिव ने पिछले दिनों एनालिस्ट कॉल में बताया था कि कंपनी मौजूदा वित्त वर्ष में करीब 80,000 करोड़ रुपये निवेश करने की योजना बना रही है। अदाणी एंटरप्राइजेज का एनर्जी, डेटा सेंटर से लेकर एयरपोर्ट तक कारोबार में दखल है।

अदाणी एंटरप्राइजेज के डिप्टी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सौरभ शाह का कहना था कि कंपनी मौजूदा वित्त वर्ष में अपने निवेश का एक बड़ा एनर्जी और एयरपोर्ट सेक्टर पर खर्च करेगी। यह रकम तकरीबन 50,000 करोड़ रुपये तक रहेगी। अदाणी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड सोलर मॉड्यूल बनाती है, जो सूर्य के प्रकाश को बिजली और ग्रीन हाइड्रोजन में बदलती करती है।

खस्ताहाल हुई पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, सभी सरकारी कंपनियां बेचकर चलाएगा खर्च

परिवहन विशेष न्यूज

पाकिस्तान सरकार ने अपनी रणनीतिक संस्थाओं को छोड़कर सभी सरकारी कंपनियों को बेचने का फैसला किया है। पाकिस्तान इस वक्त भारी वित्तीय संकट से जूझ रहा है और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने उसके कर्ज चुकाने की क्षमता पर गंभीर संदेह जताया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का कहना है कि सरकारी कंपनियों को बेचने से टैक्सपेयर का बोझ कम होगा।

नई दिल्ली। पाकिस्तान सरकार ने अपनी रणनीतिक संस्थाओं को छोड़कर सभी सरकारी कंपनियों को बेचने का फैसला किया है। पाकिस्तान इस वक्त भारी वित्तीय संकट से जूझ रहा है और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने उसके कर्ज चुकाने की क्षमता पर गंभीर संदेह जताया है।

सरकारी कंपनियां क्यों बेच रहा पाक?

पाकिस्तान ने पहले अपनी डांवाडोल अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए सिर्फ घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों को बेचने का फैसला किया था। लेकिन, अब प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का कहना है कि सरकार ने अपनी योजना का विस्तार किया है और अब वह रणनीतिक संस्थाओं को छोड़कर सभी सरकारी कंपनियों को बेचेगी।

पाकिस्तान सरकार ने सरकारी संस्थाओं का 2024 से 2029 तक निजीकरण करने का रोडमैप बनाया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में निजीकरण की प्रक्रिया की समीक्षा हुई। इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने बयान जारी करके बताया कि सभी सरकारी कंपनियों को बेचा जाएगा, चाहे वे घाटे में हों या फायदे में।

शरीफ ने कहा कि सरकारी कंपनियों को बेचने से टैक्सपेयर का पैसा बचेगा और उन पर कम बोझ पड़ेगा। हालांकि, पाकिस्तान सरकार ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि किन रणनीतिक और गैर-रणनीतिक माना जाएगा।

क्या यह IMF का दबाव है?

IMF की मिशन टीम पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म फंड की योजना पर चर्चा के लिए इस्लामाबाद आई हुई है। उससे चर्चा के एक दिन बाद पाकिस्तान सरकार ने सरकारी कंपनियों के निजीकरण का एलान किया है। IMF काफी लंबे से पाकिस्तान सरकार को घाटे वाली सरकारी कंपनियों का निजीकरण करने की सलाह दे रहा था, जो लगातार राजकोषीय कमी और बाहरी कर्ज से जूझ रहा है।

पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा भंडार भी बस कुछ महीनों की जरूरत पूरा करने भर का है। IMF का कहना है कि पाकिस्तान में सरकारी कंपनियों के पास अधिकांश मध्य पूर्व देशों की तुलना में बड़ी संपत्ति है। यह 2019 में जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद का 44 प्रतिशत थी। फिर भी रोजगार पैदा करने के मामले में उनकी हिस्सेदारी काफी कम है। IMF का अनुमान है कि 2019 तकरीबन आधी सरकारी कंपनियां घाटे में चल रही थीं।

पाकिस्तान में कितनी सरकारी कंपनियां है?

पाकिस्तान सरकार ने अपनी निजीकरण सूची में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस समेत 25 संस्थाओं और संपत्तियों को सूचीबद्ध किया है। पाकिस्तान सरकार लगातार कई साल से घाटे वाली सरकारी कंपनियों को चलाने के लिए अरबों डॉलर झोंक रही है। इसमें से सबसे अधिक घाटा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को चलाने में ही हो रहा है।

पाकिस्तान की अधिक सरकारी कंपनियां बिजली क्षेत्र में हैं। इनमें चार पावर प्लांट शामिल हैं, साथ ही 10 प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां भी हैं। इस लिस्ट में न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में स्थित मूल्यवान रूजवेल्ट होटल और दो बीमा कंपनियां भी शामिल हैं। रूजवेल्ट होटल का मालिकाना हक एयरलाइंस के पास है।

सत्ता की चाह में जुटी बेमेल राजनीतिक पार्टियां लंबी नहीं टिकती, 9 साल में 6 प्रधानमंत्री एक रिकार्ड

परिवहन विशेष। एसडी सेठी।

वर्तमान में सत्ता की हसरत में जुटी बेमेल राजनीतिक पार्टियां सत्ता तक पहुंच तो जाति हैं, पर टिक नहीं पाती । लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारें आती हैं और जाती है। देश में हर पांच साल में चुनाव भी होते हैं। मगर राजनीति के फलसफे का एक दौर ऐसा भी था कि जब देश को झोली भर-भर कर खूब प्रधानमंत्री मिले।इस दौरान 2 दिसंबर, 1989 से लेकर 19 मार्च, 1998 तक यानि 9 साल में देश को 6 प्रधानमंत्री मिले। ऐसी बेमेल राजनीतिक पार्टियों के खेल के बाद 1998 के बाद सरकारों में जब प्रधानमंत्री के तौर पर अटल बिहारी वाजपेई- ,मनमोहन सिंह, और फिर नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व मिला। वर्तमान में भी फिर वहीं 1989 वाला दौर और बे-मेल विचारधारा से सराबोर राजनीतिक दल मतदाताओ का दरवाजा खटखटा रहे है। ऐसे हालात में लोकतंत्र की प्रहरी (जनता) देश की खातिर उनके लिए कतई दरवाजा ना खोले। वरना एक दिशाहीन काल से सामना करना पड सकता है। तो जानते 9 साल यानि 1989 से 1998 के दौरान देश के 6 प्रधानमंत्री की कुर्सी तक कैसे पहुंचे?

(1) विश्व नाथ प्रताप सिंहः- वीपी सिंह के नाम से चर्चित जनता दल की भाजपा समर्थित सरकार में 2 दिसंबर, 1989 को प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। उनकी सरकार सिर्फ 343 दिन ही चल सकी थी। उनसे बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया था। और वीपी सिंह की सरकार 10 नवंबर, 1990 को गिर गई थी।

(2) चन्द्रशेखरः- वीपी सिंह के बाद जनतादल के ही नेता चन्द्रशेखर ने कांग्रेस की मदद से सरकार बनाई थी।10 नवंबर, 1990 को चन्द्रशेखर ने पीएम पद की शपथ ली। मगर 6 मार्च, 1991 यानि सिर्फ साढे तीन महीने के भीतर ही कांग्रेस ने समर्थन वापस लेकर उनकी सरकार गिरा दी थी। चन्द्रशेखर की सरकार सिर्फ 223 दिनों का कार्यकाल पूरा कर सकी थी। मरहूम राजीव गांधी की जासूसी के आरोप में चन्द्रशेखर को इस्तीफा देना पडा था।

(3) पीवी नरसिम्हा रावः- दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री बनने वाले पहले नेता थे।21 जून, 1991 में उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी थी। वह 16 मई, 1996 तक इस पद पर बने रहे। राव की सरकार चार साल 330 दिनों तक ही चली।

(4) अटल बिहारी वाजपेयीः- ने पहली बार 16 मई, 1996 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। मगर गठबंधन से बनी उनकी सरकार सिर्फ 13 दिनों तक टिकी थी। सदन में बहुमत न होने की वजह से सिर्फ 1 वोट से गिर गई थी।

(5) एचडी देवगौड़ा :- जनता दल के एचडी देवगौड़ा ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उनकी सरकार भी सिर्फ 324 दिन चली। और 21 अप्रैल, 1997 में प्रधानमंत्री का पद छोडना पडा।

(6) इन्द्र कुमार गुजराल :- ने 21 अप्रैल, 1997 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। 19 मार्च, 1998 में उन्हें भी पद छोडना पडा था। गुजराल की सरकार सिर्फ 332 दिनों तक चली थी। यहां भी कांग्रेस ने उनसे समर्थन वापिस ले लिया था। आपको बता दें कि चौधरी चरण सिंह- 28 जुलाई 1979से 14 जनवरी 1980 तक देश के पांचवें प्रधानमंत्री बने थे। वह भी कांग्रेस द्वारा समर्थन वापिस लिए जाने के बाद सिर्फ उन्होंने साढे तीन महीने तक ही पीएम के पद को संभाला था।

कॉलेजियम ने 'अयोग्य' लोगों को बना दिया जज ! सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हिमाचल के दो न्यायाधीश, CJI से दखल की मांग....

परिवहन विशेष न्यूज

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में कॉलेजियम द्वारा दो जजों की नियुक्ति पर विवाद खड़ा हो गया है, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया गया है। राज्य के दो जिला जजों चिराग भानु सिंह और अरविंद मल्होत्रा ने हाई कोर्ट के फैसले पर आपत्ति जताई है।मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सोलन और बिलासपुर के जिला जज चिराग भानु सिंह और अरविंद मल्होत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है कि हाई कोर्ट जज के पद के लिए उनकी अनदेखी की गई है। वे राज्य में सबसे वरिष्ठ जिला न्यायाधीश होने का दावा करते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय कॉलेजियम ने उनके बजाय अन्य, अधिक जूनियर व्यक्तियों को जज के रूप में नियुक्त कर दिया है।

दोनों न्यायाधीशों ने आरोप लगाया है कि नियुक्ति प्रक्रिया में उचित नियमों का पालन नहीं किया गया और सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों की अनदेखी की गई। उन्होंने कहा कि मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय को उनके नामों की सिफारिश की गई थी। जजों ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि CJI चंद्रचूड़ के कॉलेजियम की सिफारिश के बाद देश के कानून मंत्रालय ने भी नामों का समर्थन किया है। कानून मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय कॉलेजियम को पत्र लिखकर मल्होत्रा और सिंह के नामों पर विचार करने का आग्रह किया था।

उन्होंने आगे कहा कि उनके नाम पहली बार जुलाई 2023 में और फिर जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुझाए गए थे। हालांकि, इसके बावजूद, हिमाचल उच्च न्यायालय ने उनके नामों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए उन्हें पदोन्नत नहीं किया। मल्होत्रा और सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने उनकी जगह उनसे कनिष्ठ दो व्यक्तियों को नियुक्त किया है, जिनके बारे में उनका दावा है कि वे 'अयोग्य' हैं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय पर योग्यता की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके उत्कृष्ट ट्रैक रिकॉर्ड के बावजूद, उनके नामों को गलत तरीके से नजरअंदाज किया गया। दोनों न्यायाधीशों ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा की गई नियुक्तियों पर रोक लगाने का अनुरोध किया है और उच्चतम न्यायालय से उनके मुद्दे का समाधान खोजने का आग्रह किया है। इस मामले में CJI डीवाई चंद्रचूड़ के संभावित हस्तक्षेप की मांग की गई हैं।

'मोदीनॉमिक्स का रोजगार सृजनात्मक प्रभाव: प्रतिमान में बदलाव'

घरेलू शोध संस्थान स्कॉच की एक रिपोर्ट में सोमवार को दावा किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में 51.40 करोड़ रोजगार मिले हैं. 'मोदीनॉमिक्स का रोजगार सृजनात्मक प्रभावः प्रतिमान में बदलाव' शीर्षक से जारी यह रिपोर्ट 80 केस अध्ययन पर आधारित है. इसमें कर्ज लेने वाले उधारकर्ताओं और विभिन्न सरकारी योजनाओं के आंकड़ों को शामिल किया गया है.

2014-24 में 51.40 करोड़ रोजगार

स्कॉच ग्रुप ने एक बयान में कहा कि वर्ष 2014-24 के दौरान कुल 51.40 करोड़ रोजगार पैदा हुए हैं. इनमें 19.79 करोड़ रोजगार शासन-आधारित हस्तक्षेपों की वजह से सृजित हुए हैं. बाकी 31.61 करोड़ रोजगार में ऋण-आधारित हस्तक्षेपों का योगदान रहा है. स्कॉच ग्रुप सामाजिक-आर्थिक मुद्दों पर काम करने वाला एक घरेलू शोध संस्थान है. यह 1997 से ही समावेशी विकास पर काम कर रहा है.

लोन से औसतन 6.6 प्रत्यक्ष रोजगार

कंपनी की ओर से जारी किए गए बयान के मुताबिक, वर्तमान अध्ययन से यह भी पता चलता है कि सूक्ष्म कर्ज का इस्तेमाल स्थिर और टिकाऊ रोजगार सृजन के लिए किया जा रहा है. स्कॉच ग्रुप के चेयरमैन और इस रिपोर्ट के लेखक समीर कोचर ने कहा कि हमने अपने दौरों में 80 केस अध्ययन के दस्तावेज जुटाए हैं. इसमें कर्ज लेने वाले कई उधारकर्ताओं को शामिल किया गया है और एक कर्ज राशि पर औसतन 6.6 प्रत्यक्ष रोजगार पैदा हुए हैं.

मनरेगा समेत दर्जन भर योजनाओं से बढ़ा रोजगार

इस अध्ययन में 12 केंद्रीय योजनाओं को शामिल किया गया है. इनमें मनरेगा, पीएमजीएसवाई, पीएमए-जी, पीएमएवाई-यू, आरएसईटीआई, एबीआरवाई, पीएमईजीपी, एसबीएम-जी, पीएलआई और पीएम स्वनिधि जैसी योजनाएं शामिल हैं. अध्ययनों से पता चला है कि पिछले नौ वर्षों में ऋण अंतराल (जीडीपी के अनुपात में कर्ज का अंतर) में 12.1 प्रतिशत की गिरावट आई है. इसने ऋण अंतराल में कटौती, बहुआयामी गरीबी में कमी और एनएसडीपी में वृद्धि के बीच एक सकारात्मक संबंध भी दिखाया है.

सरकारी हस्तक्षेप से सालाना 1.98 करोड़ रोजगार

कोचर ने कहा कि हमने 2014-24 की अवधि में ऋण-आधारित हस्तक्षेपों और सरकार-आधारित हस्तक्षेपों का अध्ययन किया है. जहां ऋण-आधारित हस्तक्षेपों ने प्रति वर्ष औसतन 3.16 करोड़ रोजगार जोड़े हैं, वहीं सरकार-आधारित हस्तक्षेपों से 1.98 करोड़ रोजगार पैदा हुए हैं. यह रिपोर्ट इस लिहाज से अहम है कि इसमें औपचारिक स्रोतों से संरचनात्मक ऋण के रोजगार सृजन पर प्रभाव और आंशिक रोजगार एवं इसके निदान का अध्ययन किया गया है.

जाने क्या अन्तर है जज, जस्टिस और मजिस्ट्रेट में...

जज, जस्टिस और मजिस्ट्रेट के बारे में सुनते रहते हैं। जब भी किसी पर कोई मामला बनता हो या किसी से किसी प्रकार का झगड़ा होता है, वे गुस्से में कह देते हैं कि अब कोर्ट में मिलेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि इसकी सुनवाई कौन करता है। अक्सर लोगों में इन तीन पद नामों के बीच का अंतर नहीं पता होता है। उन्हें ये लगता है कि ये तीन एक ही है बस नाम अलग-अलग है। लेकिन आपको बता कि इन तीनों नामों के बीच काफी अंतर है। जज, जस्टिस और मजिस्ट्रेट के काम करने से लेकर इनकी नियुक्ति प्रक्रियां में भी काफी अंतर है। जाने जज, जस्टिस और मजिस्ट्रेट के बीच का अंतर। भारत विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में से एक है। यहां न्यायपालिका संविधान का अंग है। न्यायपालिका का कार्य नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करना होता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला स्तर न्यायालय देश के कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए काम करते हैं। कोर्ट में आते हैं दो तरह के केस न्यायालय में दो तरह के मामले आते हैं। पहला सिविल मामले, दूसरा क्रिमिनल मामले। सिविल मामले के अंतर्गत अधिकार और नुकसान की मांग की जाती है। वहीं क्रिमिनल मामले को हिंदी में दांडिक मामले या फौजदारी मामला भी कहते हैं। इन केस के अंतर्गत दंड की मांग की जाती है।

मजिस्ट्रेट क्या होता है मजिस्ट्रेट एक न्यायाधीश की तरह केवल एक जिले के कानूनी मामलों में संभालने का काम करते हैं। लेकिन न्यायाधीश के पास इतनी पावर नहीं होती है। वहीं मजिस्ट्रेट उम्रकैद व फांसी का दंड नहीं दे सकते हैं। अगर बात करें मजिस्ट्रेट के सबसे ऊंचे पद की तो वह चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट होता है। ये मजिस्ट्रेट रेवेन्यू मामलों की सुनवाई करते हैं। इसके अलावा छोटे-मोटे सिविल मामलों की सुनवाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट व सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट करता है। मजिस्ट्रेट की नियुक्ति राज्य सरकार और हाई कोर्ट के द्वारा की जाती है। इसके लिए लॉ की डिग्री होनी जरूरी नहीं है। जस्टिस न्यायपालिका में जस्टिस सबसे ऊंचा पद होता है। ये हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हैं। इनका प्रथम कर्तव्य आम नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना होता है। मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में सीधे हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है। इसकी सुनवाई जस्टिस करता है। जज जज की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा की जाती है। जज बनने के लिए लॉ की डिग्री होनी जरूरी है। एक जज क्रिमिनल को फांसी व उम्र कैद की सजा दे सकता है। जज जटिल मामलों को संभालने का काम करते हैं।

ओड़शिा मे कोंग्रेस का बिजेड़ी बीजेपी (गठबंधन) साथ लड़ाई हो रही है और नबीन पटनायक को 5 सवाल किया : कोंग्रेस नेता जयराम रमेश

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड उडीशा

भुबनेश्वर : ओड़शिा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय मे राष्ट्रीय नेता श्री जयाराम रमेश ने प्रेस को सम्बोधन किया ।ओड़शिा मे बीजेपी बिजेड़ी एक साथ चुनाब लड़ रहे हैं , उनकी साथ हमारा लड़ाई हो रहा है । चुनाब से पहले उनका गठबंधन होना था ।नबीन पटनायक ने पार्लियामेंट मे बीजेपी का हर बिधेयक पर बिजेड़ी समर्थन करता है ।ओड़शिा का जनता को मालूम है बीजेपी बिजेड़ी एक है । चौथा चरण चुनाब के बाद मोदी जी को पता चल गया है 4 जून को उनकी प्रधानमंत्री पद एक्सपारि हो रहा है । इसीलिए मोदी जी ने मछली , मटन , मंगल सूत्र , मुस्लिम और भैंस की पर बात कर रही है ।मुख्यमंत्री के निशाने पर हैं जयराम रमेश । बीजेडी का बीजेपी को समर्थन सही नहीं है । लेबर पार्टी कृषि विरोधी कानून का समर्थन नहीं करती ? क्या आप शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में आदिवासियों का विकास चाहते हैं ?

हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट का बड़ा फैसला! ये कच्चे कर्मचारी होंगे पक्के

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए हरियाणा में उन सैकड़ों कच्चे कर्मचारियों के नियमितीकरण का रास्ता साफ कर दिया है, जो 2003 में ओमप्रकाश चौटाला सरकार में लाई गई नीति के तहत स्थायी होने के पात्र थे। आदेश दिया गया कि यदि राज्य किसी व्यक्ति को उसी पद पर नियुक्त करने का निर्णय लेता है जहां वह दो दशकों से नियुक्त था, तो यह नहीं कहा जा सकता कि उसके लिए कोई नियमित कार्य नहीं था।

यमुनानगर निवासी ओम प्रकाश व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उन्हें नियमित करने की मांग की थी। याचिका में कहा गया कि वे दो दशक से अधिक समय से राज्य में सेवा दे रहे हैं, लेकिन 2003 की नीति के बावजूद उनकी सेवाओं को नियमित नहीं किया गया। उनके कई सहकर्मियों और कई कनिष्ठों की सेवाएँ नियमित कर दी गईं, लेकिन याचिकाकर्ताओं को कोई लाभ नहीं मिला। याचिका का विरोध करते हुए हरियाणा सरकार ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को स्वीकृत पदों पर नियुक्त नहीं किया गया और आज भी वे स्वीकृत पदों पर काम नहीं कर रहे हैं. ऐसी स्थिति में उनकी सेवा नियमित नहीं की जा सकती.

हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर राज्य सरकार ने कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने के लिए कोई नीति जारी की है तो उसे हर कर्मचारी पर लागू किया जाना चाहिए. कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए. हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को उनके कनिष्ठों को नियमित करने की तिथि से नियमित करने का आदेश दिया है। नियमितीकरण की स्थिति में वित्तीय लाभ उनकी ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर करने के बाद ही मिलेगा।

संविधान में राज्य को कल्याणकारी राज्य कहा गया है और ऐसे में अगर कोई कर्मचारी एक दशक से अधिक समय तक राज्य को अपनी सेवा देता है तो उसे नियमित करने के लिए पद सृजित करना सरकार की जिम्मेदारी है. राज्य को उन्हें नियमित करने का प्रयास करना चाहिए न कि उनकी सेवाओं को नियमित करने के रास्ते में बाधाएं डालनी चाहिए हाईकोर्ट के इस फैसले से देर से ही सही लेकिन सैकड़ों कच्चे कर्मचारियों को न्याय मिल गया है. अब हम चाहते हैं कि सरकार इस फैसले को लागू करे और जो कच्चे कर्मचारी इस फैसले के दायरे से बाहर रह गए हैं और 10 से 15 साल से सरकार की सेवा कर रहे हैं, उन्हें भी जल्द पक्का किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी के चुनाव पर रोक लगाने की मांग पर विचार से किया इनकार, याचिकाकर्ता ने वापस ली अपनी याचिका

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि उन्हें अपनी शिकायत संबंधित प्राधिकरण से करनी चाहिए ।जब मामला सुनवाई पर आया तभी कोर्ट ने याचिकाकर्ता फातिमा के वकील से पूछा कि क्या आपने इस बारे में संबंधित प्राधिकरण से संपर्क किया है। पीठ ने कहा कि कोर्ट में याचिका दाखिल कर आदेश मांगने से पहले उन्हें संबंधित प्राधिकरण के पास जाना चाहिए।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने घृणा फैलाने वाले भाषणों और आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के चुनाव पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर मंगलवार को विचार करने से इनकार कर दिया। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि उन्हें अपनी शिकायत संबंधित प्राधिकरण से करनी चाहिए। जब मामला सुनवाई पर आया तभी कोर्ट ने याचिकाकर्ता फातिमा के वकील से पूछा कि क्या आपने इस बारे में संबंधित प्राधिकरण से संपर्क किया है। पीठ ने कहा कि कोर्ट में याचिका दाखिल कर आदेश मांगने से पहले उन्हें संबंधित प्राधिकरण के पास जाना चाहिए।

मोदी को छह साल के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित करे

कोर्ट का नकारात्मक रुख देखते हुए याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली। याचिका में मांग की गई थी कि चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए कि वह जनप्रतिनिधित्व कानून में मोदी को छह साल के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित करे। इसके अलावा घृणा फैलाने वाले भाषणों को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई थी उसे भी कोर्ट ने खारिज कर दिया।

"गलवान में एलएसी से आगे तैनात हैं दोनों देशों की सेनाएं, यह असामान्य स्थिति है"

जयशंकर ने कहा कि भारत ने भी चीन की तैनाती का कड़ा जवाब दिया। हमने भी अपनी सेनाएं वहां तैनात की। पिछले चार साल से सेनाएं गलवान में सामान्य बेस पोजीशन से आगे तैनात हैं। एलएसी पर यह तैनाती असामान्य है।

चीन और भारत के बीच एलएसी सीमा विवाद काफी लंबे समय से जारी है। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर बलों की तैनाती असामान्य है। देश की सुरक्षा की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। जयशंकर मंगलवार को इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत ने गलवान झड़प का जवाब वहां बलों की जवाबी तैनाती से दिया।

2020 में चीनियों ने समझौते को तोड़ दिया : जयशंकर ने कार्यक्रम में बताया कि 1962 की जंग के बाद 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन की यात्रा की। इसका उद्देश्य स्पष्ट था कि चीन और भारत संबंधों को सामान्य बनाएंगे। यात्रा का उद्देश्य सीमा मतभेदों पर चर्चा करने के साथ-साथ सीमा पर शांति के बनाए रखना था। लेकिन 2020 में चीनियों ने इस समझौते को तोड़ दिया।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023